@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

नई दिल्ली, शुक्रवार, 28 अगस्त 2026, वर्ष-1, अंक-272, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

नेपाल-तिब्बत सीमा पर अचानक आई बाढ़ में 288 भारतीय लापता, 200 फंसे

नई दिल्ली, एजेंसी।

नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ के बाद कम से कम 288 भारतीय अब भी लापता हैं, जबकि लगभग 200 अन्य चीन की ओर फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि भारत दोनों देशों के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है, ताकि बचाव अभियान में समन्वय किया जा सके। इसने कहा कि बचाव अभियान में तेजी आने के साथ भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और संकट से निपटने में उसकी मदद कर रहा है। नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ ने तीन जिलों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 270 हो गई।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शीर्ष अधिकारियों तथा काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ उच्चस्तरीय बैठक के बाद कहा कि भारत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए "पुरजोर प्रयास" कर रहा है। भारत ने बुधवार रात से दो सैन्य परिवहन विमानों के जरिए कुल 47.5 टन आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेजी है और अधिक राहत सामग्री भेजने की प्रक्रिया जारी है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत की तत्काल प्राथमिकता लापता भारतीयों का पता लगाना और उन्हें बचाना तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में

फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना है। तथा पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों के पर्यटक समूह शामिल हैं। उन्होंने कहा, 288 भारतीय नागरिकों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इनमें वे 73 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जो त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना में काम कर रहे थे। काठमांडू स्थित हमारा दूतावास इन लोगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रमुख के संपर्क में है।

उन्होंने कहा, इसके अलावा, तमिलनाडु के 37 और 49 भारतीय नागरिकों के दो अलग-अलग समूह हैं, जो सम्राट और फ्लाई एवरेस्ट ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे। जायसवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल के 32 भारतीय नागरिकों का एक अलग समूह भी था, जो सम्राट ट्रैवल्स की मदद से रसुवा जिले के तिमुरे गया था। उन्होंने कहा कि वहीं, कुछ अन्य राज्यों के 61 भारतीय नागरिकों का एक और समूह भी था।

नेपाल बाढ़ : मौत का आंकड़ा 392 तक पहुंचा

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई। वहीं, बचावकर्मी 290 भारतीय नागरिकों समेत लापता सैकड़ों लोगों का पता लगाने के लिए युद्धस्तर पर जुटे हुए हैं। मृतकों में 389 लोगों की मौत नेपाल में अचानक आई बाढ़ में हुई, जबकि पड़ोसी तिब्बत में तीन लोग मारे गए। नेपाल पुलिस के एक बयान में कहा गया कि प्रभावित इलाकों से अब तक 50 विदेशियों समेत 796 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिये बचाया गया है, जबकि अन्य 796 लोगों को सड़क मार्ग से सुरक्षित निकाला गया है। हालांकि, बयान में विदेशी नागरिकों की राष्ट्रीयता का उल्लेख नहीं किया गया। बयान में बताया गया कि नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास हिमनद के टूटने से चट्टानें खिसक गई और हिमस्खलन हुआ, जिसके कारण बुधवार को पानी, कीचड़ और मलबे का तेज बहाव मध्य नेपाल की ओर आया। इससे कई कस्बे और गांव तबाह हो गए, मकान, वाहन, सड़कें एवं पुल बह गए तथा जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा।

सार समाचार

मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में चार लोगों की मौत

इंफाल,एजेंसी। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर एक वाहन पर किये गये हमले में कम से कम चार लोग मारे गए, जबकि एक अन्य घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मकुई अशांग और थाबंबा नगा इलाकों के बीच एक सुनसान जगह पर उग्रवादियों ने घात लगाकर एक गाड़ी पर हमला किया, जिसमें चार लोग मारे गये एवं एक व्यक्ति घायल हो गया। अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में हताहत हुए सभी लियांगमाई नगा समुदाय से थे। अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की पहचान टैडसोंगबोउ रिंगकांगमाई (एक निजी विद्यालय के संस्थापक और प्राचार्य), एम विजुनमाई, अनिल विजुनमाई और विसोबोउ चारेनामाई (जो चावांगकिइनिंग विलेज अथॉरिटी के अध्यक्ष थे) के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि शवों को सेनापति ज़िला अस्पताल लाया जा रहा है। घायल व्यक्ति की पहचान गायकमांग रिंगकांगमई के रूप में हुई।

डीयू छात्रा की घर में घुसकर चाकू मारकर हत्या

नई दिल्ली,एजेंसी। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की 21 वर्षीय छात्रा की उसके घर पर एक परिचित ने कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस को संदेह है कि आरोपी पीड़िता के किसी अन्य व्यक्ति से बात करने से नाराज था। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान आकिब उर्फ इमरान (26) के रूप में हुई है, जो फरार है और उसे पकड़ने के लिए लगभग 15 पुलिस टीम गठित की गई हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़िता दिल्ली विश्वविद्यालय के 'स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग' में दूसरे वर्ष की छात्रा थी और अपने परिवार के साथ मंगला अस्पताल के पास एक इमारत में रहती थी। जांच के अनुसार, युवती आरोपी को करीब डेढ़ साल से जानती थी। आरोपी पहले जिम ट्रेनर था और वर्तमान में बेरोजगार था। पुलिस ने बताया कि दोनों 20 अगस्त को एक होटल में भी मिले थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पिछले दो महीने से युवती के किसी और से बात करने को लेकर कथित तौर पर उससे नाराज था। बुधवार शाम को आरोपी उस समय युवती के घर गया जब वह अकेली थी। पुलिस ने कहा कि दोनों के बीच बहस होने लगी, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर उस पर चाकू से हमला किया और भाग गया।

परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए: खरगे

नई दिल्ली,एजेंसी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों की संख्या में अगले 25 वर्षों तक कोई बदलाव नहीं हो। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्ताव को संसद में पेश करने से पहले सभी राजनीतिक दलों तथा राज्य सरकारों को उस पर विस्तार से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए तथा 543 सीटों के आधार पर 2029 से महिला आरक्षण लागू किया जाए।

खरगे ने पत्र में कहा, मैं अपने पहले के अनुरोध को दोहराना चाहता हूं कि परिसीमन से संबंधित आपके मन में जो भी प्रस्ताव हैं, उन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सभी राजनीतिक दलों तथा राज्य सरकारों को ऐसे प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दें। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बात का उल्लेख किया कि उन्होंने इससे पहले 16 जुलाई, 2026 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सरकार के परिसीमन संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया था।

खरगे ने कहा कि वह अब इस अनुरोध को दोहरा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने पिछली रात एक टेलीविजन साक्षात्कार में सार्वजनिक रूप से कहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा, शायद यही कारण है कि मानसून सत्र का अभी तक सत्रावसान नहीं किया गया है। खरगे ने कहा कि कांग्रेस का इस मामले पर रुख बिल्कुल स्पष्ट है।

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

फिरोजपुर,एजेंसी। पंजाब में तीन लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने लंबित महंगाई भत्ते (डीए) को जारी करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को राज्यव्यापी हड़ताल की जिसके कारण विभिन्न सरकारी विभागों का कामकाज प्रभावित हुआ और अस्पतालों में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) की सेवाएं भी बाधित रहीं। मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच जालंधर में प्रस्तावित बैठक उस समय रद्द कर दी गई, जब मान ने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को स्पष्ट किया कि बातचीत तभी होगी। जब वे हड़ताल खत्म कर देंगे। कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया और बिना किसी शर्त के बैठक किए जाने पर जोर दिया। पंजाब सांझा मुलाजिम मंच के बैनर तले 150 से अधिक कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से लंबित अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से 'महा हड़ताल' में हिस्सा लिया।

भारत का रक्षा उत्पादन चार गुना बढ़ा : राजनाथ

कहा, भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है

जबलपुर, एजेंसी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन पिछले एक दशक में करीब चार गुना बढ़कर लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है। सिंह ने यहां 'व्हीकल फैक्टरी जबलपुर' (वीएफजे) में टी-सीरीज के युद्धक टैंकों के मरम्मत व रखरखाव के लिए 472 करोड़ रुपये की लागत वाली सुविधा की आधारशिला रखने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा, घरेलू रक्षा (हथियार और गोला-बारूद) उत्पादन 2014 में 46,000 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह रक्षा निर्यात भी 2014 के करीब 1,000 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 39,000 करोड़ रुपये हो गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

सिंह ने कहा कि भारत न केवल देश में हथियारों का निर्माण कर रहा है, बल्कि उनके रखरखाव, मरम्मत और उन्नयन की क्षमता भी विकसित कर रहा है।

रक्षा मंत्री ने कहा, आज की परियोजना आत्मनिर्भरता की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले वर्षों में भारत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में एक मजबूत देश के रूप में उभरेगा।

सिंह ने टैंक मरम्मत परियोजना को भारत के आत्मनिर्भर औद्योगिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि नई सुविधा निर्धारित समयसीमा में और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरी होगी। इसके तहत हर साल 'टी-72' और 'टी-90' के 80 टैंकों की मरम्मत की जाएगा।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना को हर साल ऐसे करीब 230 टैंकों की मरम्मत की जरूरत होती है। चेन्नई के अवाडी स्थित हेवी व्हीकल्स फैक्टरी (एचवीएफ) फिलहाल सालाना करीब 150 टैंकों की मरम्मत करती है और वीएफजे में बनने वाली नई सुविधा शेष कमी को पूरा करेगी। टैंक मरम्मत सुविधा वीएफजे में स्थापित की जा रही है, जो आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल) के तहत संचालित प्रमुख सैन्य वाहन विनिर्माण इकाई है। अधिकारियों ने बताया कि 1969 में स्थापित इस फैक्टरी में शुरुआत में जर्मनी की एम.ए.एन. के सहयोग से 'शक्तिमान 3टी' वाहन तथा जापान की निसान मोटर्स कंपनी के सहयोग से 'निसान 1टी' और जोंगा वाहनों का उत्पादन किया जाता था। उन्होंने बताया कि फैक्टरी परिसर 330 एकड़ में फैला है, जबकि इससे लगा एस्टेट 600 एकड़ में है।

लंबे युद्ध से निपटने के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और औद्योगिक क्षमता आवश्यक

जबलपुर, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि दुनिया में मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, सुदृढ़ औद्योगिक क्षमता और तेजी से नवाचार करने की क्षमता रखने वाले देश लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों का बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम होते हैं। उन्होंने यह बात चार साल से अधिक समय से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में कही।

राजनाथ ने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि महत्वपूर्ण रक्षा जरूरतों के लिए भारत की सशस्त्र सेनाएं विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर न रहें।

रक्षा मंत्री ने कहा, हमारा लक्ष्य देश में ही रक्षा उपकरणों का निर्माण करना, उनकी मरम्मत और रखरखाव का कार्य देश में ही करना, मौजूदा प्रणालियों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों से उन्नत करना और अगली पीढ़ी की क्षमताओं का स्वदेशी रूप से विकास करना है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास वैश्विक विनिर्माण केंद्र, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार और भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में भारत के उभरने को दर्शाते हैं। राजनाथ ने 57 साल पुराने व्हीकल फैक्टरी जबलपुर (वीएफजे) में टी-सीरीज के युद्धक टैंकों के ओवरहाल के लिए 472 करोड़ रुपये की लागत वाली सुविधा की आधारशिला रखने के बाद ये बातें कहीं।

केंद्र सरकार ने दिल्ली रेस क्लब का कब्जा लिया

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली रेस क्लब के 53 एकड़ परिसर का कब्जा लेने के कुछ ही देर बाद वहां ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया। इसके साथ ही, इस सौ साल पुराने संस्थान में घुड़दौड़ की गतिविधियां नाटकीय ढंग से समाप्त हो गईं।

मंगलवार को पटियाला हाउस अदालत ने क्लब की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें संपदा अधिकारी द्वारा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली) अधिनियम के तहत 11 अगस्त को जारी बेदखली के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद, केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित परिसर का कब्जा ले लिया।

क्लब के एक अधिकारी ने बताया कि बुलडोजर ने क्लब की कई ऐतिहासिक इमारतों को गिरा दिया, जिनमें अस्तबल, बुकमेकर्स रिंग, विनिंग पोस्ट, फोटो-फिनिश कैमरा, सैडलिंग एनक्लोजर और दूसरी सुविधाएं शामिल थीं, जो कभी दिल्ली में घुड़दौड़ का मुख्य केंद्र हुआ करती थीं। क्लब से जुड़े एक सूत्र ने कहा, क्लब और रेसिंग से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए यह बहुत परेशान करने वाला दृश्य था। क्लब के अधिकारी ने कहा, हमारे पास 250 से अधिक घोड़े थे। इनमें से लगभग 200 घोड़ों को उनके मालिकों ने वापस ले लिया है।

जबकि करीब 50 घोड़े अभी भी क्लब में हैं। उन्होंने कहा, ''हमें सब कुछ ठीक करने के लिए 14 सितंबर तक का समय दिया गया है। हम अगले एक-दो हफ्तों में बाकी घोड़ों को उनके मालिकों के पास भेजने की योजना बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 1940 के दशक में नये सिरे से बनाए गए क्लब के अस्तबलों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि घोड़े दिल्ली की भीषण गर्मी से बचे रहें। अधिकारी ने कहा, इस जगह को बहुत सावधानी से बनाया गया था ताकि घोड़ों को गर्मी से बचाया जा सके और अस्तबल में हवा-पानी का अच्छा इंतजाम रहे। अपनी नस्ल और रेसिंग रिकॉर्ड के आधार पर 3 लाख से 50 लाख रुपये तक की कीमत वाले ये 'थोरब्रेड' घोड़े देश के सबसे बेहतरीन और महंगे रेस के घोड़ों में से हैं।

सूत्रों ने बताया कि हर कुछ दिनों में, रेसकोर्स से घोड़ों को ले जाने वाली गाड़ी (हॉर्स फ़्लोट) निकलती है और देश भर के रेसिंग सेंटर पर बने नए परिसरों में कीमती रेस-घोड़ों को पहुंचाती है।

यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री 29 से 30 अगस्त तक उज्बेकिस्तान का दौरा करेंगे, जहां वह विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करेंगे

उज्बेकिस्तान और किर्गिजस्तान की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार से शुरू होने वाली चार-दिवसीय विदेश यात्रा के पहले चरण में उज्बेकिस्तान जाएंगे, जहां वह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए बातचीत करेंगे। इसके बाद वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान जाएंगे।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के पहले चरण में मोदी 29 से 30 अगस्त तक उज्बेकिस्तान का दौरा करेंगे, जहां वह विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान से किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे, जहां वह एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में क्षेत्र में बदलती सुरक्षा स्थिति पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किए जाने की उम्मीद है।

इसने कहा कि एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शिखर बैठक को संबोधित करेंगे, जहां वह सुरक्षा, संपर्क और अवसरों से जुड़ी भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उन नेताओं में शामिल हैं, जिनके शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना है।

इस वर्ष एससीओ की स्थापना

की 25वीं वर्षगांठ भी है। भारत वर्ष 2017 से संगठन का पूर्ण सदस्य है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहां वह इस मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसरों से जुड़ी भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में कहा कि एससीओ की स्थापना मुख्य रूप से आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से की गई थी, जो अब भी एक चुनौती बने हुए हैं। मोदी शिखर सम्मेलन से इतर एससीओ के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ऐसी जानकारी है कि पुतिन उन नेताओं में शामिल होंगे, जिनके साथ प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान अलग से द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

प्रधानमंत्री छठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे, जो मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना होगा। जॉर्ज ने कहा, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 29 और 30 अगस्त को ताशकंद की राजकीय यात्रा करेंगे। यह प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की राह के लिए एजेंडा तय करेंगे।

इसने कहा कि मोदी और मिर्जियोयेव विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान-2030 के साझा विकास संबंधी दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी अपने विचार साझा करेंगे।

भाजपा ने राहुल पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया

नई दिल्ली,एजेंसी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक वेबसाइट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। यह वेबसाइट उनके 'छात्रों की गूंज' अभियान के दौरान दिए गए बयानों की सच्चाई की जांच (फैक्ट-चेक) करने का दावा करती है। पार्टी ने कहा कि अब उनके 'झूठ' का जवाब तथ्यों के साथ दिया जाएगा। पार्टी ने गांधी पर जोरदार हमला करने के लिए अपने कई प्रवक्ताओं को मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि गांधी की बातें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति 'निराशा और ईर्ष्या' से प्रेरित हैं।

उन्होंने 'झूठ की गूंज' नामक वेबसाइट को गांधी के अभियान के लिए 'बड़ी चुनौती' बताया और 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में इसका लिंक भी साझा किया। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि गांधी 'झूठ के ध्वजवाहक' हैं और आरोप लगाया कि उनके बयान मोदी के प्रति निराशा और ईर्ष्या से प्रेरित हैं।

त्रिवेदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति निराशा और ईर्ष्या से भरे झूठ के ध्वजवाहक राहुल गांधी चाहे कितना भी झूठ फैलाते रहें, अब हर असत्य का पर्दाफाश तथ्यों के जरिए किया जा रहा है।

'झूठ की गूंज' वेबसाइट गांधी के दावों की सच्चाई को एक-एक करके सामने ला रही है।

पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि गांधी के दावों का अब तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा।

जीवन में सबसे बड़ा काम है साधारण बनना: राम नाथ कोविंद

दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे।

नई दिल्ली,एजेंसी।

दिल्ली विश्वविद्यालय और 'ओम प्रकाश कोहली स्मृति समिति' द्वारा 'ओम प्रकाश कोहली मेमोरियल लेक्चर' (स्मृति व्याख्यान) के तहत "विकसित भारत @ 2047 और नागरिकों की भूमिका" विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस रीगल लॉज स्थित कन्वेंशन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने की।

इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन में साधारण बनना सबसे बड़ा काम है। यदि आप किसी बड़े पद पर हैं और फिर भी साधारण बने हुए हैं तो ये श्रेष्ठ कार्य है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश कोहली किसी भी पद पर रहे, उनके भीतर एक विनम्र शिक्षक सदा बना रहा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामूहिक संकल्प है।

उन्होंने कहा कि देश ने पिछले एक दशक में आर्थिक, सामाजिक, रक्षा और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और अब लक्ष्य केवल विकास करना नहीं, बल्कि उसे टिकाऊ बनाना है। श्री कोविंद ने ओम प्रकाश कोहली को याद करते हुए कहा कि कोहली जी केवल विचारक नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक संस्था थे और आपातकाल जैसे कठिन दौर में भी अपने दायित्वों और सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख माध्यम बताते हुए कहा कि शिक्षक की जिम्मेदारी केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि ज्ञान को मूल्यों और कौशल से जोड़कर विद्यार्थियों को बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाना है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने का स्थान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन की दिशा दिखाने वाले संस्थान हैं। डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि 2047 तक भारत तो विकसित होकर रहेगा। सबको उसमें अपनी भूमिका तलाशनी है। उन्होंने आह्वान किया कि डीयू के शिक्षक और विद्यार्थी विकसित भारत के निर्माण में कैप्टन की भूमिका निभाएं। प्रो. योगेश सिंह ने ओम प्रकाश कोहली की मानवीय संवेदनशीलता को याद करते हुए कहा कि जीवन से संवेदना समाप्त हो जाए तो जीवन का अर्थ भी समाप्त हो जाता है।

उन्होंने हिटलर और अब्राहम लिंकन का उदाहरण देते हुए कहा कि नेतृत्व में करुणा आवश्यक है। प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि विकसित भारत के लिए जीडीपी को 25 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के साथ ऐसा समाज बनाना होगा, जहां कोई भूखा न रहे और कोई शिक्षा से वंचित न हो। उन्होंने नागरिकों के लिए अनुशासन, राष्ट्रीय चरित्र और सदाचार को आवश्यक बताया। कार्यक्रम के आरंभ में ओम प्रकाश कोहली स्मृति समिति के संयोजक राज कुमार भाटिया ने स्वागत भाषण और परिचय प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम के समापन पर ओम प्रकाश कोहली स्मृति समिति के संयोजक इंदर मोहन कपाही ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सुश्री स्वाति कोविंद, साउथ कैंपस की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी, डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणि, सीओएल की निदेशक प्रो. पायल मागो और रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति/शिक्षाविद उपस्थित रहे।

एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने नवयुग स्कूल में विद्यार्थियों के साथ मनाया रक्षाबंधन

नई दिल्ली,एजेंसी।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने गुरुवार को लक्ष्मीबाई नगर स्थित नवयुग स्कूल के विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल में राखी बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने रंग-बिरंगी राखियां बनाईं और चहल को राखी बांधी। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्कूल की प्रधानाचार्या, शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रशंसा की। इस अवसर पर कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्रेम का त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी का संदेश भी देता है।

उन्होंने कहा कि बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर देना एक मजबूत और विकसित भारत के लिए जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत से पढ़ाई करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया।

स्कूल की प्रधानाचार्या अर्चना ने चहल का स्कूल आने और विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के बाद चहल ने स्कूल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान एनडीएमसी के सिविल, स्वास्थ्य और इलेक्ट्रिकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने स्कूल की साफ-सफाई, रखरखाव, भवन और अन्य जरूरी सुविधाओं का जायजा लिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विजन के अनुरूप, चहल ने संबंधित अधिकारियों को स्कूल की सुविधाओं को और बेहतर बनाने, आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य समय पर पूरा करने तथा स्कूल के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए।

फरीदाबाद में बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन

फरीदाबाद,एजेंसी।

बढ़ती महंगाई के खिलाफ गुरुवार को फरीदाबाद जन संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने एनआईटी-5 स्थित माता गुजरी चौक मोड़ पर नुक्कड़ नाटक कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। समिति के लोगों ने नाटक के जरिए आम आदमी की परेशानी को सामने रखा और कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने गरीब और मजदूर वर्ग की कमर तोड़ दी है। लोगों को जागरूक करने के साथ सरकार से महंगाई पर तत्काल नियंत्रण करने की मांग की गई।

नुक्कड़ नाटक के दौरान उन्होंने रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की बढ़ती कीमतों को मुद्दा बनाया। नाटक में चीनी, सरसों का तेल, दाल और पेट्रोल की कीमतों का जिक्र करते हुए बताया गया कि खाने-पीने के सामान से लेकर वाहन चलाने तक हर जगह आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है।

कार्यकर्ताओं का कहना था कि आमदनी सीमित है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। नाटक के दौरान एक व्यक्ति 'महंगाई डायन' की वेशभूषा में नजर आया। उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए महंगाई के कारणों को लेकर सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह का गेटअप सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि लोगों को यह समझाने के लिए किया गया है कि आखिर महंगाई की जड़ क्या है और इसका सबसे ज्यादा असर किस वर्ग पर पड़ रहा है।

समिति के लोगों ने बताया कि चीनी 62 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच चुकी है, सरसों का तेल 250 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गया है और दालों के दाम भी 150 रुपए प्रति किलो से ऊपर बताए जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत भी 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि महंगा पेट्रोल लोगों के बजट पर सीधा असर डाल रहा है।

समिति के लोगों ने कहा कि महंगाई की सबसे बड़ी मार मजदूर और कम आय वाले परिवारों पर पड़ रही है। समिति के लोगों ने सरकार से मांग की कि जरूरी वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

स्मार्ट सिटी के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़

बल्लभगढ़,एजेंसी।

रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए घर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ते ही गुरुवार को बल्लभगढ़ और एनआईटी बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आगरा, अलीगढ़, सोहना और गुरुग्राम की ओर जाने वाली बसों में पैर रखने तक की जगह नहीं रही। यही हाल रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया। हालात ये रहे कि महिला कोच में भी पुरुष यात्री जबरन चढ़ गए। भीड़ अधिक होने से टैक्सी और निजी वाहन सेवा का यात्रियों ने लाभ लिया, हालांकि उन्हें बाकी दिनों के मुकाबले जेब ज्यादा ढ़ीली करनी पड़ी।

बसों में सीट नहीं मिलने पर कई यात्री खड़े होकर सफर करते दिखाई दिए। यही नहीं, बसों की छतों पर भी यात्रियों ने अपना ठिकाना बनाया। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने करीब 15 अतिरिक्त बसें विभिन्न व्यस्त मार्गों पर उतारीं। इससे यात्रियों को थोड़ी राहत मिली, हालांकि देररात तक बस अड्डों पर भीड़ बनी रही। गुरुवार दोपहर तक बल्लभगढ़ और एनआईटी बस अड्डों से आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर 50 से अधिक बसें रवाना हो चुकी थीं। इसके अलावा सोहना।

गुरुग्राम, पलवल और नूंह सहित अन्य मार्गों पर भी अतिरिक्त बसें चलाई गईं। रोडवेज प्रबंधन ने यात्रियों की संख्या को देखते हुए कॉलेज के विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाली कुछ बसों को भी व्यस्त मार्गों पर लगा दिया। इस दौरान अपनी जान जोखिम में डाल कर बसों की छत पर भी यात्रा की। फरीदाबाद से 30 से अधिक मार्गों पर रोजाना करीब 125 बसों का परिचालन होता है।

इनमें कई बसें अपने निर्धारित मार्ग के बस अड्डों पर रात में ठहरती हैं। रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की बढ़ी संख्या को देखते हुए ऐसी बसों का रात्रि ठहराव भी निरस्त कर उन्हें वापस बुलाया गया है। इससे दिन के समय अधिक बसें यात्रियों के लिए उपलब्ध हो सकेंगी। हरियाणा रोडवेज की बसों में रक्षाबंधन के अवसर पर गुरुवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार रात 12 बजे तक बहनों के लिए यात्रा निशुल्क रखी गई है। निशुल्क यात्रा के चलते बस अड्डों पर महिला यात्रियों की संख्या बढ़ी रही।

बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए मायके की ओर रवाना हुईं। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं के लिए बस यात्रा निशुल्क की है। खास बात यह है कि महिला यात्री के साथ एक सहयोगी को भी निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई। इसका महिलाओं के साथ उनके सहयोगियों ने भी काफी लाभ उठाया। फरीदाबाद से अलीगढ़ और आगरा की ओर जाने वाली उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में इस सुविधा के कारण महिला यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा देखने को मिला।

युवकों ने दो भाइयों के सिर पर कुर्सी मारी

नोएडा,एजेंसी।

सदरपुर में रहने वाले दो भाइयों को दो युवकों ने रास्ते में रोक लिया। आरोपियों ने उनके सिर पर हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो लोगों को नामजद करते हुए जांच शुरू कर दी है। जिला बरेली के फतेहगंज पूर्वी निवासी पारस गुप्ता ने पुलिस को बताया कि वह वर्तमान में सेक्टर-45 स्थित सदरपुर में किराये पर रहते हैं। वह 24 अगस्त की सुबह सेक्टर-45 सोम बाजार से शिवमंदिर जा रहे थे। रास्ते में भाई अजय गुप्ता से मोहित और शिवम नाम के दो लड़के उनके साथ गाली-गलौज कर रहे थे। उन्हें डरा धमका रहे थे। यह देखकर वह बीच-बचाव कराने लगे। आरोप है कि शिवम नाम के लड़के ने उन दोनों भाइयों के सिर पर जोर से कुर्सी मार दी।

किसान भूखंड के लिए दो सितंबर को पैदल मार्च करेंगे

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी।

जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को शेष चार फीसदी आबादी भूखंड दिए जाने की मांग तेज हो गई है। इसको लेकर घोड़ी बछेड़ा गांव के किसानों ने दो सितंबर को शांतिपूर्ण पैदल मार्च का ऐलान किया है। गुरुवार को प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। बता दें कि जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड देने का प्रावधान है। वहीं, कोर्ट के आदेश पर कुछ किसानों को चार फीसदी अतिरिक्त आबादी भूखंड का लाभ दिया गया है। किसान संगठनों की मांग है कि जमीन अधिग्रहण से प्रभावित सभी किसानों को शेष चार फीसदी आबादी भूखंड का लाभ दिया जाए।

किसानों ने बताया कि दो सितंबर को सुबह 10 बजे घोड़ी बछेड़ा शहीद पार्क से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला जाएगा।

प्रधानमंत्री के लोकार्पण शिलापट्ट को हटाने का आरोप

गाजियाबाद,एजेंसी।

राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान से प्रधानमंत्री का लोकार्पण (वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम) शिलापट्ट हटाने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पूर्व कर्मचारी ने मधुबन बापूधाम पुलिस से की है। हालांकि, कर्मचारी का दावा है कि पुलिस जांच शुरू होने पर पंजीकरण काउंटर के बाहर स्टील की फेम में नई शिलापट्ट को रातों रात लगवा दिया गया। आयुष मंत्रालय के अधीन कमला नेहरूनगर स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान संचालित है। इसमें मरीजों को इलाज के साथ मास्टर डिग्री के लिए छात्र-छात्राओं के शिक्षण का कार्य भी चल रहा है।

संस्थान के पूर्व अधिकारी अमित उपाध्याय ने पुलिस कमिश्नर के साथ मधुबन बापूधाम पुलिस को शिकायत की है कि संस्थान के लोकार्पण का सफेद पत्थर का शिलापट्ट अस्पताल प्रबंधन ने हटा दिया है। यह पत्थर मुख्य गेट के बाहर दीवार पर लगा था। लेकिन अब दीवार पर प्लास्टर के साथ पुताई की जा चुकी है। इसके साक्ष्य भी उन्होंने पुलिस को व्हाट्सऐप और मेल किए हैं।

शिकायत में शिलापट्ट हटाने में शामिल डॉक्टरों के नाम भी खोले गए हैं। आरोप है कि शिकायत के बाद की शुरू हुई जांच के बाद प्रबंधन ने आनन-फानन में पंजीकरण गैलरी के बाहर बायीं ओर काले रंग के स्टील फ्रेम में नए शिलापट्ट को लगा दिया। लेकिन सफेद पत्थर की असली शिलापट्ट अब भी अस्पताल से गायब है। शिलापट्ट हटाने के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्हें शिकायत की कोई कॉपी नहीं मिली है। कुछ पूर्व कर्मचारी यूनानी अस्पताल की छवि को खराब करने के लिए आए-दिन साजिश रचते रहते हैं। इस मामले में दो दिन पहले आयुष मंत्रालय की टीम ने भी दौरा किया था।

सड़कों पर स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने का काम तेज

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी।

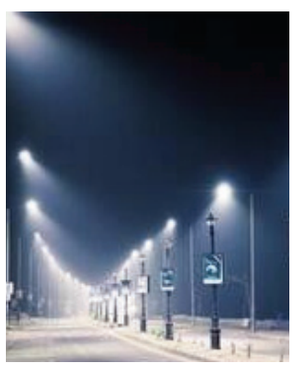

रक्षाबंधन और आगामी त्योहारों को देखते हुए ग्रेटर नोएडा में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम तेज कर दिया गया है। बंद पड़ी और कम रोशनी वाली एलईडी स्ट्रीट लाइट के स्थान पर नई लाइट लगाई जा रही हैं। सड़कों को जगमग करने के लिए पर्यवेक्षक, तकनीकी पर्यवेक्षक और स्ट्रीट लाइट का काम देखने वाली कंपनी के कर्मचारियों की विशेष टीमें गठित की गई हैं।

अधिकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में बिसरख, दादरी-सूरजपुर-कुलेसरा (डीएससी) मार्ग, 130 मीटर चौड़ी सड़क, चार मूर्ति चौक, सेक्टर-16बी, 4, 10, हैबतपुर, इटेड़ा, खोदना खुर्द आदि क्षेत्र में मुख्य मार्गों के साथ अंदर की सड़कों पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक किया जा रहा है। बिसरख गांव और सेक्टर-10 में लंबे से बंद पड़ीं स्ट्रीट लाइट को ठीक कर दिया गया है। अब रोशनी होने लगी है।

बता दें कि उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए थे। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए यह विशेष अभियान पिछले दो दिनों से चल रहा है। वहीं, ग्रेटर नोएडा ईस्ट इलाके, सेक्टर डेल्टा-2, सेक्टर-36 और डाढ़ा गांव सहित अन्य सेक्टरों में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक किया जा रहा है। वरिष्ठ प्रबंधक अजीत भाई पटेल ने बताया कि अंधेरे वाले स्थान चिह्नित कर वहां पर रोशनी करने का काम शुरू कर दिया गया है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नवरात्रि और दीवाली तक काम पूरा कर लिया जाएगा। त्योहारों के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और सड़कों पर पर्याप्त रोशनी रहे, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 250 से अधिक स्ट्रीट लाइट को ठीक किया जा चुका है।

स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने के के लिए सीईओ रवि कुमार एनजी ने सभी वर्क सर्किल के प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। त्योहारों को देखते हुए शहर की सभी सड़कों और गांवों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम चल रहा है। किसी भी सड़क पर अंधेरा न रहे यह सुनिश्चित किया जा रहा है। निगरानी बढ़ा दी गई है। वर्क सर्किल के अधिकारियों द्वारा रात में निरीक्षण किया जा रहा है।

ककराला में आयुष्मान आरोग्य मंदिर अगले महीने तक तैयार होगा

नोएडा,एजेंसी।

प्राधिकरण शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ककराला में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवा रहा है। यह अगले महीने के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका संचालन स्वास्थ्य विभाग करेगा। अधिकारियों ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पीएम जन आरोग्य कार्यक्रम के अंतर्गत नगरीय आयुष्मान मंदिर संचालित होने हैं।

शहर की जनता को चिकित्सा सुविधाएं एवं राज्य स्तर से संचालित योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए प्राधिकरण की ओर से कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए फेज-2 क्षेत्र के ककराला खासपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाया जा रहा है। यह पोर्टेबल क्लीनिक के रूप में बनाया जा रहा है। प्राधिकरण के महाप्रबंधक ए.के अरोड़ा ने बताया कि यह आरोग्य मंदिर सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका संचालन स्वास्थ्य विभाग से कराया जाएगा। इसमें ओपीडी रूम, वेलनेस रूम, डे केयर रूम, प्रतीक्षालय, स्टाफ रूम आदि की व्यवस्था होगी।

बारिश व प्रदूषण के दिनों में घर से काम की मिले छूट, घटेगा ट्रैफिक: मैनी

गुरुग्राम,एजेंसी।

बारिश के दौरान जलभराव और सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से लोगों को राहत देने के लिए गुरुग्राम में घर से काम करने की व्यवस्था को मंजूरी दी जानी चाहिए। जिन कर्मचारियों का काम घर से आसानी से हो सकता है, उन्हें खराब मौसम और अधिक प्रदूषण वाले दिनों में दफ्तर आने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को एक स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर इसे लागू करना चाहिए। यह कहना है प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन दीपक मैनी का।

दीपक मैनी ने गुरुवार को कहा कि गुरुग्राम में बारिश के दौरान कई सडक़ों पर जलभराव हो जाता है। इससे यातायात की रफ्तार कम होने के साथ कई जगह लंबा जाम लग जाता है। सर्दियों में वायु प्रदूषण बढऩे पर भी बड़ी संख्या में लोगों के सडक़ पर आने-जाने से वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण को और बढ़ाता है। ऐसे में घर से काम की व्यवस्था दोनों स्थितियों में राहत दे सकती है।

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, सलाहकार सेवाओं और अन्य दफ्तरों में ऐसा काम होता है, जिसे कर्मचारी घर से भी कर सकते हैं। प्रशासन इन संस्थानों की पहचान कर ऐसी व्यवस्था तैयार कर सकता है कि बारिश या वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने पर कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए। घर से काम करने की व्यवस्था लागू होने से सुबह और शाम के व्यस्त समय में सडक़ों पर निजी कारों, टैक्सियों और अन्य वाहनों की संख्या कम हो सकती है। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और जाम की समस्या में कमी आएगी। साथ ही वाहनों से निकलने वाले धुएं में कमी आने से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है।

रक्षा बंधन पर बहन ने भाई को किडनी देकर दी नई जिंदगी

फरीदाबाद,एजेंसी।

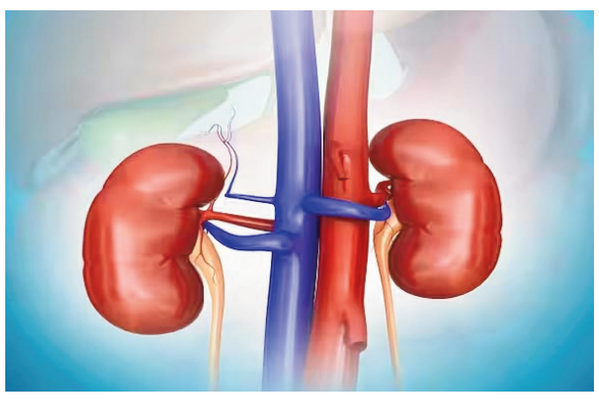

रक्षा बंधन के मौके पर भाई-बहन के रिश्ते की एक भावुक मिसाल सामने आई है। 47 वर्षीय रेखा मिश्रा ने अपने 40 वर्षीय भाई विनय पांडेय को किडनी दान कर उन्हें जिंदगी की नई उम्मीद दी। विनय किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। चिकित्सकीय जांच के बाद किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत सामने आई तो बहन रेखा ने अपनी किडनी दान करने का फैसला लिया। एकॉर्ड अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी की गई। आवश्यक जांच और चिकित्सकीय औपचारिकताओं के बाद रेखा को किडनी दान के लिए उपयुक्त पाया गया। भाई को स्वस्थ जीवन देने के लिए बहन का यह निर्णय रक्षा बंधन के पर्व पर भाई-बहन के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉ. जितेंद्र कुमार ने कहा कि अंगदान किसी जरूरतमंद मरीज के लिए जीवन का दूसरा अवसर हो सकता है। रेखा मिश्रा का अपने भाई के लिए किडनी दान करने का निर्णय सराहनीय है। ऐसे मामलों से समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ती है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज और डोनर दोनों की नियमित चिकित्सकीय निगरानी बेहद जरूरी होती है। रक्षा बंधन पर बहन ने राखी के साथ अपने भाई को जीवन का अनमोल उपहार दिया। यह मामला अंगदान की महत्ता और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग की प्रेरक मिसाल बन गया है।

RNI.No DLHIN/25/A2841

स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मे. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।

संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508
मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com

संपादक देवेंद्र सिंह तोमर

इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

रोहिणी जेल में रिश्वत का खेल, 4 आरोपितों की जमानत खारिज

न्यायालय के अनुसार, मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और कई गवाहों तथा संबंधित विचाराधीन कैदियों से पूछताछ की जानी बाकी है।

नई दिल्ली,साहस समाचार।

रोहिणी जेल में कैदियों और उनके स्वजन से कथित तौर पर रिश्वत वसूलने के मामले में अदालत ने 4 आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए प्रथम दृष्टया इसे किसी एक कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेने का सामान्य मामला नहीं, बल्कि जेल अधिकारियों और निजी लोगों के एक संगठित समूह द्वारा चलाया जा रहा कथित रिश्वत तंत्र बताया है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपितों ने आपराधिक साजिश के तहत विचाराधीन कैदियों और उनके परिवारों पर दबाव बनाकर कथित रूप से बार-बार बड़ी रकम वसूली।

न्यायालय के अनुसार, मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और कई गवाहों तथा संबंधित विचाराधीन कैदियों से पूछताछ की जानी बाकी है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) एसीबी-01 विद्या प्रकाश की अदालत ने हेड वार्डर योगेश, सहायक अधीक्षक सुनील कुमार तथा निजी आरोपित हरेंद्र बंसल और विप्लव खारी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने माना कि इन 4 आरोपितों की भूमिका उन आरोपितों से अलग और अधिक गंभीर प्रतीत होती है, जिन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और इस स्तर पर आरोपितों को राहत देना जांच को प्रभावित कर सकता है।

अदालत के समक्ष जांच के दौरान सामने आए तथ्यों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि कथित रिश्वत की रकम अलग-अलग बैंक खातों में मंगाई जाती थी। इसके बाद रकम को नकद निकालकर संबंधित जेल अधिकारियों तक पहुंचाने का आरोप है। जांच में यह भी सामने आने की बात कही गई कि रकम के लेन-देन के लिए केवल आरोपितों के बैंक खातों का ही इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उनके परिचितों और रिश्तेदारों के खातों का भी सहारा लिया गया। इससे जांच एजेंसियों को कथित रिश्वत तंत्र में शामिल लोगों और धन के प्रवाह की कड़ियों को जोड़ने में मदद मिल रही है।

न्यायालय ने जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कहा कि कैदियों और उनके स्वजन पर कथित रूप से दबाव बनाया जाता था। आरोप है कि जेल के भीतर परेशान किए जाने या अन्य कठिनाइयों का सामना करने के बाद कैदियों के परिवारों से रकम देने के लिए दबाव बनाया जाता था। अदालत के अनुसार, इस पूरी व्यवस्था में जेल के कुछ सरकारी कर्मचारियों के साथ निजी लोगों की भूमिका भी सामने आई है। कथित तौर पर निजी लोगों के माध्यम से रकम मंगाने और उसे आगे पहुंचाने की व्यवस्था संचालित की जाती थी।

अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि मामले में जब्त किए गए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा कई गवाहों और संबंधित विचाराधीन कैदियों से पूछताछ भी लंबित है। न्यायालय ने इन परिस्थितियों को देखते हुए जांच की वर्तमान स्थिति को महत्वपूर्ण माना और 4 आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। मामले में आगे की जांच जारी है और आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

बात मुद्दे की

आलोक गौड़

छह साल का बच्चा तो संविधान समझ गया, सत्ता क्यों भूल गई?

नई दिल्ली। बिहार के पटना में छात्रों के आंदोलन के बीच छह साल का आदित्य जब तिरंगा लेकर सरकार से सवाल पूछने पहुंचा तो उसे इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि आज लोकतंत्र में सवाल पूछना कितना बड़ा अपराध बना दिया गया है। वह न पत्थर लेकर निकला था, न कोई हथियार लेकर। वह अपने भविष्य की बात करने निकला था। वह छात्रों के हक की बात कर रहा था। वह सरकार से जवाब मांग रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सवाल आदित्य पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर खड़ा कर दिया।

रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस उसे प्रदर्शन स्थल से अपने साथ ले गई और कई घंटे बाद परिवार को सौंपा गया। आदित्य और उसके परिवार की ओर से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस इन आरोपों से इनकार करती है और उसका कहना है कि बच्चे को हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि प्रदर्शन की अफरातफरी से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक छह साल का बच्चा आखिर व्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया कि पुलिस को उसे प्रदर्शन स्थल से हटाना पड़ा? उसके हाथ में संविधान था। यही बात इस घटना को सामान्य पुलिस कार्रवाई से कहीं बड़ा बना देती है।

संविधान नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार देता है। लोकतंत्र सरकार को जवाबदेह बनाता है। विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना नागरिक अधिकार है। फिर वह बच्चा जो इन्हीं अधिकारों की भाषा बोल रहा था, व्यवस्था को असहज क्यों कर रहा था? आज सत्ता को हर सवाल का जवाब देने के बजाय पुलिस, बैरिकेड और प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल करने का विकल्प क्यों ज्यादा आसान दिखाई देता है? यह सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है। यह उस राजनीतिक संस्कृति का सवाल है जिसमें सरकारों को सवाल पसंद नहीं आते और पुलिस को सवाल पूछने वालों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है।

आदित्य की उम्र छह साल है। वह अभी उस उम्र में है जब बच्चे स्कूल में लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन पटना की सड़क पर वह उन अधिकारों को किताब से निकालकर जमीन पर इस्तेमाल करता दिखाई दिया। विडंबना यह है कि जिस संविधान की शपथ लेकर जनप्रतिनिधि सत्ता में आते हैं, उसी संविधान के अधिकारों को एक बच्चा उनसे ज्यादा गंभीरता से समझता दिखाई दे रहा है। वह पूछ रहा है कि सरकार छात्रों की बात क्यों नहीं सुनती? रोजगार क्यों नहीं मिलता? परीक्षाओं और भर्ती व्यवस्था में युवाओं को परेशानी क्यों होती है?

इन सवालों का जवाब पुलिस की गाड़ी नहीं है।

इनका जवाब लाठी नहीं है।

इनका जवाब किसी बच्चे को डराना भी नहीं है।

इनका जवाब सरकार को देना होगा। और अगर सरकार के पास जवाब है तो उसे एक छह साल के बच्चे से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

दरअसल, आदित्य की कहानी उस नई पीढ़ी की कहानी है जिसे हम किताबों में संविधान पढ़ा रहे हैं और सड़कों पर संविधान की ताकत आजमा रही है। यह पीढ़ी सवाल पूछ रही है। यह जानना चाहती है कि उसके माता-पिता टैक्स क्यों देते हैं, सरकार उनसे क्या वादा करती है और उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा।

इसे चुप कराने की कोशिश की गई तो सवाल खत्म नहीं होगा। बल्कि सवाल और बड़ा होगा। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक नागरिक वह नहीं होता जो सवाल पूछता है। सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब नागरिक सवाल पूछना ही छोड़ दे।

पटना का यह बच्चा इसलिए चर्चा में नहीं होना चाहिए कि उसकी उम्र छह साल है। वह इसलिए चर्चा में होना चाहिए क्योंकि उसने हमें याद दिलाया है कि संविधान नागरिकों की उम्र देखकर अधिकार नहीं देता।

छह साल का बच्चा अगर अपने अधिकार की भाषा समझ सकता है तो सत्ता को भी संविधान की भाषा समझनी होगी। सरकारें आती-जाती रहेंगी। मुख्यमंत्री बदलेंगे, मंत्री बदलेंगे, पुलिस अधिकारी बदलेंगे। लेकिन संविधान रहेगा। और संविधान यह नहीं कहता कि सत्ता से सवाल पूछने के लिए पहले वयस्क होना जरूरी है।

मुद्दा यही है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि अब उसे एक छह साल के बच्चे के सवाल से भी डर लगने लगा है?

अजीत भारती की अग्रिम जमानत पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली,साहस समाचार।

यूट्यूबर अजीत भारती ने जातिसूचक और आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में दर्ज मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले के जांच अधिकारी को तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की गई है। अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 अगस्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों और प्राथमिकी में लगाई गई धाराओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध के लिए आवश्यक तत्व पूरे नहीं होते। अजीत भारती की ओर से अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई और प्रत्युष प्रसन्ना ने अदालत के समक्ष दलील दी कि पुलिस ने उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत आवश्यक सूचना नहीं दी है। अदालत ने इस संबंध में कहा कि यदि जांच अधिकारी की ओर से ऐसा नोटिस जारी किया जाता है तो उसकी प्रति अदालत में भी प्रस्तुत की जाए।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इससे वह नोटिस जारी किए जाने की तारीख और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कानून के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को लेकर जांच अधिकारी की प्रथमदृष्टया संतुष्टि की स्थिति को देख सकेगा। यह मामला दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। शिकायत आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालकराम बौद्ध की ओर से दी गई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 22 अगस्त को प्रसारित एक यूट्यूब कार्यक्रम में अजीत भारती ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और डॉ. भीमराव आंबेडकर को लेकर जातिसूचक एवं आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। शिकायत में महिलाओं के संबंध में कथित अश्लील टिप्पणी करने और धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान जाति, आरक्षण, विवाह और अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को लेकर लगातार टिप्पणियां की गईं।

मुख्यमंत्री ने बच्चों संग मनाया रक्षाबंधन का पर्व

नई दिल्ली,साहस समाचार।

रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से आए बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस अवसर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से राखियां बांधीं, मिठाई खिलाई और कविताएं सुनाई। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ संवाद किया और उनके स्कूल, पढ़ाई और परिवार की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बच्चों को उपहार देकर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया।

उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि उनका भविष्य उनकी पढ़ाई और मेहनत से बनेगा तथा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर बच्चे को आगे बढ़ने के अवसर मिलें। बच्चों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए स्वयं बनाई हुई राखियां भी भेंट कीं। बच्चों ने बताया कि इन राखियों को उन्होंने काफी मेहनत से तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने बच्चों की रचनात्मकता और जागरूकता की सराहना करते हुए उन्हें दिल्ली को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री ने बच्चों को उपहार और चॉकलेट दिए। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे अपनी मां के लिए भी उपहार लेकर जाएं और उन्हें अपनी ओर से भेंट करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से आए इन बच्चों ने जिस प्यार, अपनापन और उत्साह के साथ रक्षाबंधन मनाया, वह उनके लिए बेहद भावुक और यादगार क्षण है। बच्चों का प्यार और आशीर्वाद किसी सौगात से कम नहीं है।

20 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी दोषी करार

नई दिल्ली,साहस समाचार।

द्वारका जिला अदालत ने 20 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी मोहिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी अपने बचाव में विश्वसनीय और सुसंगत कहानी पेश करने में विफल रहा। साथ ही वह यह भी साबित नहीं कर सका कि विवादित चेक का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नितेश गोयल की अदालत संजय कुमार की ओर से दायर शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। शिकायत के मुताबिक, आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच वर्षों से पारिवारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध थे।

मार्च 2013 में आरोपी ने आर्थिक जरूरत बताते हुए 20 लाख रुपये का दोस्ताना ऋण लिया था और बदले में द्वारका स्थित एक दुकान के मूल दस्तावेज सुरक्षा के तौर पर दिए थे। बाद में ऋण चुकाने के लिए आरोपी ने 20 लाख रुपये का चेक जारी किया। शिकायतकर्ता ने चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, लेकिन नवंबर 2021 में वह अपर्याप्त फंड की टिप्पणी के साथ बाउंस हो गया। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजा गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने दावा किया कि चेक सुरक्षा के तौर पर दिया गया था और शिकायतकर्ता ने उसका दुरुपयोग किया। हालांकि, अदालत ने पाया कि मुकदमे के विभिन्न चरणों में आरोपी ने अलग-अलग और परस्पर विरोधी दलीलें पेश कीं। पहले उसने कहा कि वह शिकायतकर्ता को ऋण देने वाला था, लेकिन बाद में उसने 12.5 लाख रुपये और आभूषण देने जैसी नई बातें जोड़ीं। अदालत ने माना कि इस तरह के बदलाव उसके बचाव की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यदि वास्तव में चेक का दुरुपयोग हुआ होता तो आरोपी पुलिस में शिकायत करता या बैंक को भुगतान रोकने के निर्देश देता।

राखी बांधकर परमजीत सिंह पम्मा को समाजसेवा के लिए दिया आशीर्वाद

नई दिल्ली, साहस समाचार।

राजौरी गार्डन स्थित ब्रह्माकुमारी आश्रम में भाई-बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व श्रद्धा एवं आत्मीयता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजौरी गार्डन सेवाकेंद्र की डायरेक्टर बीके शक्ति दीदी जी सहित ब्रह्माकुमारी बहनों ने नेशनल अकाली दल के अध्यक्ष एवं 'एंग्री मैन' के खिताब से सम्मानित परमजीत सिंह पम्मा को राखी बांधकर उनके सुखद, स्वस्थ एवं उज्ज्वल जीवन की कामना की तथा समाजहित में निरंतर कार्य करने का आशीर्वाद दिया।

बीके शक्ति दीदी जी ने कहा कि परमजीत सिंह पम्मा लंबे समय से समाज के हित और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। उनका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना है। उन्होंने कहा कि समाजसेवा के क्षेत्र में किए जा रहे उनके प्रयास सराहनीय हैं और उन्हें इसी तरह जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए।

इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा ने ब्रह्माकुमारी बहनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी का पवित्र बंधन है। उन्होंने कहा कि बहनों से मिले इस स्नेह और आशीर्वाद से उन्हें समाजहित के कार्यों को और अधिक ऊर्जा एवं समर्पण के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है।

पम्मा ने कहा कि वे समाज में भाईचारा, आपसी सहयोग और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने ब्रह्माकुमारी बहनों द्वारा समाज में शांति, सद्भाव और सकारात्मक सोच का संदेश फैलाने के प्रयासों की भी सराहना की।

कार्यक्रम के दौरान आश्रम का वातावरण आध्यात्मिक एवं आत्मीय भावनाओं से ओत-प्रोत रहा। उपस्थित लोगों ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समाज में प्रेम, शांति, भाईचारे और मानवता की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया।

आईआईटी दिल्ली में प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी

नई दिल्ली,साहस समाचार।

आईआईटी दिल्ली में एमएससी भौतिकी के छात्र की मौत के मामले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने परिसर में सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और प्रदर्शन के वीडियो बनाने पर छात्र भड़क गए और उन्होंने इस बारे में सवाल उठाए। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन का रवैया छात्र हितैषी नहीं है। इस बीच संस्थान ने मामले की जांच के लिए बाहरी समिति का पुनर्गठन करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता को अध्यक्ष बनाया है।

बुधवार रात निदेशक की ओर से छात्रों को भेजे ई-मेल के अनुसार समिति में एम्स, नई दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रताप शर्मा, दो छात्र प्रतिनिधि और आईआईटी दिल्ली के रजिस्ट्रार भी शामिल हैं। इससे पहले समिति के अध्यक्ष बनाए गए उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने खुद को अलग कर लिया था। छात्र भौतिकी विभाग की विभागाध्यक्ष और छात्र कल्याण से जुड़े अधिकारियों के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी से बातचीत का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सादी वर्दी में पुलिस की मौजूदगी और पहचान पत्र दिखाने को लेकर बातचीत होती दिख रही है।

आईआईटी दिल्ली ने कहा कि हर छात्र उसके लिए महत्वपूर्ण है और छात्र कल्याण उसकी प्राथमिकता है। संस्थान ने शैक्षणिक दबाव कम करने, मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य और शिकायत निवारण की व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

2025 में नया पाठ्यक्रम लागू होने के बाद प्रथम सेमेस्टर का क्रेडिट भार कम किया गया, जीवन कौशल के पाठ्यक्रम जोड़े गए और प्रथम वर्ष की विभागीय कक्षाओं में छात्रों की संख्या 30 से 60 तक सीमित की गई। सप्ताहांत की परीक्षाएं कम की गईं और क्रेडिट वितरण में लचीलापन रखा गया। 2024-25 से बीटेक के लिए न्यूनतम सीजीपीए की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई।

स्टूडेंट-टीचर इंटरैक्शन काउंसिल के माध्यम से नियमित बैठकें, शिक्षकों के खुले संवाद का समय, परियोजना मार्गदर्शन, छात्रावास स्तर पर सहभागिता और कक्षा समितियों के माध्यम से छात्रों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है।

संस्थान के अनुसार 24 घंटे परामर्शदाता और मनोचिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें एम्स और विमहांस के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। बाहरी मानसिक स्वास्थ्य उपचार का पूरा खर्च लौटाने और आपात स्थिति में त्वरित सहायता की व्यवस्था है। छात्र साथी कार्यक्रम का विस्तार कर 2025 में परास्नातक और अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। योग और ध्यान के माध्यम से भी कल्याण पर काम किया जा रहा है।

जानलेवा हमले के मामले में दो दशक बाद आरोपी दोषमुक्त

नई दिल्ली,साहस समाचार।

साकेत जिला अदालत ने वर्ष 2005 में जानलेवा हमले के मामले में करीब 21 साल बाद आरोपी नरेंद्र सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। अतिरिक्त सिविल जज स्वयं सिद्ध त्रिपाठी की अदालत ने माना कि मामले में घायल शिकायतकर्ता ने अदालत में आरोपी की पहचान नहीं की, न कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी पेश किया गया और न ही ऐसे ठोस साक्ष्य सामने जो आरोपी के अपराध को साबित कर सकें।

अभियोजन के अनुसार चार अक्तूबर 2005 को मंगला पुरी बस टर्मिनल के पास पंचर बना रहे अनुराग पांडेय पर राम कुमार, उसके पुत्र निरंजन और नरेंद्र उर्फ काले ने लोहे की रॉड व अन्य हथियारों से हमला किया था। हमले में अनुराग को गंभीर चोटें आई थीं। इस संबंध में डाबड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। मुकदमे के दौरान आरोपी राम कुमार और निरंजन की मृत्यु हो गई, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई। इसके बाद मामला केवल नरेंद्र सिंह के खिलाफ जारी रहा। मामले ने उस समय अहम मोड़ लिया जब शिकायतकर्ता आरोपी की पहचान नहीं कर पाया।

उसने गवाही में कहा कि कुछ लोगों ने पीछे से उस पर हमला किया था, लेकिन वह हमलावरों की पहचान नहीं कर सकता। जिरह के दौरान उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने पुलिस को किसी आरोपी का नाम नहीं बताया था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता इस मामले का मुख्य प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित था। जब वही आरोपी की पहचान नहीं कर पाया और उसके बयान की पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, तब आरोपी के खिलाफ गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप सिद्ध नहीं हो सके। फैसले में अदालत ने कहा कि आपराधिक मामलों में आरोप सिद्ध करने का दायित्व पूरी तरह अभियोजन पर होता है। चूंकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं था जो आरोपी को अपराध से जोड़ सके, इसलिए नरेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी किया जाता है।

संपादकीय

क्या भारत को अब एक समान नागरिक संहिता पर निर्णायक कदम उठाना चाहिए?

देवेंद्र सिंह तमर

भारत विविधताओं का देश है। यहां धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक रीति-रिवाज अलग-अलग हैं। यही विविधता भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है और कई बार नीति निर्माण के सामने बड़ी चुनौती भी बन जाती है। एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code—UCC) का प्रश्न इसी चुनौती के केंद्र में है। वर्षों से इस मुद्दे पर राजनीति, बहस और वैचारिक टकराव होता रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत को इस दिशा में निर्णायक कदम उठा देना चाहिए?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के लिए यह प्रयास करने की बात कही गई है कि देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जाए। हालांकि यह संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल है, इसलिए इसे सीधे लागू करने योग्य मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। इसके बावजूद संविधान निर्माताओं ने इस विषय को भविष्य के भारत की सामाजिक व्यवस्था से जोड़कर देखा था। आज, आज़ादी के लगभग आठ दशक बाद, इस बहस का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। वर्तमान में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे कई नागरिक मामलों में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक ही देश के नागरिक होने के बावजूद कुछ पारिवारिक मामलों में अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। समर्थकों का तर्क है कि एक समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार देकर संविधान की मूल भावना समानता और न्याय को मजबूत करेगी।

इस मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। किसी भी लोकतांत्रिक और आधुनिक समाज में नागरिकों के अधिकार उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर अलग-अलग नहीं होने चाहिए। विवाह, तलाक, संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों के मामलों में महिलाओं को समान कानूनी सुरक्षा मिलना आवश्यक है। यदि कोई प्रथा या व्यक्तिगत कानून लैंगिक समानता के सिद्धांत से टकराता है, तो राज्य का दायित्व है कि वह संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और गरिमा के अधिकार की रक्षा करे। इसलिए UCC को केवल धार्मिक कानूनों के प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि नारी सम्मान और समान नागरिक अधिकारों के प्रश्न के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

लेकिन दूसरी ओर इस विषय से जुड़ी चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में व्यक्तिगत कानून केवल कानूनी प्रावधान नहीं हैं; वे कई समुदायों की परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़े हैं। इसलिए यदि एक समान नागरिक संहिता को किसी विशेष समुदाय के कानून को दूसरे समुदाय पर थोपने के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से अविश्वास और विरोध पैदा होगा। सरकार और समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसी संहिता तैयार करने की है जो वास्तव में समानता पर आधारित हो, किसी धार्मिक बहुमत की परंपरा पर नहीं।

निर्णायक कदम का अर्थ जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। UCC जैसे संवेदनशील विषय पर कानून बनाने से पहले व्यापक संवाद आवश्यक है। इसमें सभी धार्मिक समुदायों, महिला संगठनों, कानून विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। आदिवासी समुदायों और विभिन्न क्षेत्रों की विशेष सामाजिक परंपराओं को भी गंभीरता से समझना होगा। लोकतंत्र में कानून की ताकत केवल संसद से पारित होने में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता में भी होती है। सरकार चाहे तो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकती है। सबसे पहले उन प्रावधानों पर सहमति बनाई जा सकती है जिनका सीधा संबंध लैंगिक समानता और नागरिक अधिकारों से है। विवाह की न्यूनतम आयु, पंजीकरण, तलाक की न्यायपूर्ण प्रक्रिया, बच्चों और महिलाओं के अधिकार तथा संपत्ति में समानता जैसे मुद्दों पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति अपेक्षाकृत आसानी से बनाई जा सकती है।

हिमालय की आपदा और नेपाल-भारत के लिए चेतावनी

डॉ. अरविंद नाथ तिवारी

नेपाल-तिब्बत सीमा के पास आई विनाशकारी बाढ़ ने एक बार फिर पूरे हिमालयी क्षेत्र को झकझोर दिया है। रसुवा क्षेत्र में ल्हेन्डे खोला, भोटेकोशी और त्रिशूली नदी तंत्र में अचानक आया पानी और मलबे का सैलाब अपने साथ घर, वाहन, सड़कें, पुल और इंसानी जिंदगियां बहा ले गया। 27 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रिपोर्टों में नेपाल में 157 मौतों और चीन के तिब्बत क्षेत्र में तीन मौतों की जानकारी सामने आई है, जबकि 750 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में 133 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इस त्रासदी की भयावहता इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह केवल नेपाल की समस्या नहीं है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सीमाओं को नहीं पहचानतीं। नेपाल में आई आपदा का सीधा असर भारत, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के नदी क्षेत्रों पर पड़ सकता है। इसलिए यह समय केवल राहत और बचाव का नहीं, बल्कि भविष्य की आपदाओं के लिए स्थायी रणनीति बनाने का है।

हिमालय की नदियां राजनीति से बड़ी हैं। उनका पानी सीमा नहीं देखता, इसलिए आपदा प्रबंधन भी सीमा में बंधा नहीं रह सकता। अब समय है कि नेपाल, चीन और भारत आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर एक साझा हिमालयी आपदा चेतावनी तंत्र बनाएं। क्योंकि अगली बार चेतावनी के लिए हमारे पास शायद कुछ मिनट भी न हों।

एक तथ्य को स्पष्ट करना जरूरी है। पिछली बड़ी रसुवा-भोटेकोशी आपदा 8 जुलाई 2025 को हुई थी। नेपाल सरकार की आपदा रिपोर्ट के अनुसार उस समय तिब्बत में एक सुप्राग्लेशियल झील के अचानक खाली होने से ल्हेन्डे नदी में फ्लैश फ्लड आया था। कम से कम नौ लोगों की मौत हुई और 19 लोग लापता हुए थे

यानी लगभग एक वर्ष के भीतर उसी व्यापक सीमा क्षेत्र में दो बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। साल 2025 में भी नेपाल के अधिकारी और विशेषज्ञों ने सीमा पार ग्लेशियल झीलों के खतरे की ओर संकेत किया था। लेकिन सवाल है कि क्या उस चेतावनी को पर्याप्त गंभीरता से लिया गया?

नेपाल के अपने आपदा रिकॉर्ड बताते हैं कि बाढ़ कोई नई चुनौती नहीं है। 1978 में तिनाऊ बेसिन, 1980 में कोसी, 1985 में तादी, 1987 में सुनकोशी और 1993 में मध्य नेपाल में भीषण बाढ़ ने तबाही मचाई थी। 1993 की आपदा में लगभग 1,336 लोगों की जान गई थी। इसलिए लाव 2026 की त्रासदी को महज एक आकस्मिक प्राकृतिक घटना मानकर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी भूल होगी।

इस बार शुरुआत में भूकंप को बाढ़ का कारण माना गया लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विश्लेषण के अनुसार दर्ज हुआ भूकंपीय संकेत स्वयं एक बड़े बर्फ-पत्थर के भूस्खलन से पैदा हुआ था, यानी पहाड़ का विशाल हिस्सा खिसका, उसने नदी तंत्र को प्रभावित किया और फिर पानी, बर्फ, पत्थर तथा मलबे की विनाशकारी दीवार नीचे की ओर चली गई।

यही हिमालय की नई चुनौती है- भूकंप, ग्लेशियर, भूस्खलन और बाढ़ अब अलग-अलग खतरे नहीं रह गए हैं; वे एक-दूसरे को जन्म देने वाली आपदाओं की श्रृंखला बन सकते हैं। साल 2025 में भी तिब्बत से निकलने वाली ग्लेशियल झील के अचानक फटने से भोटेकोशी में बाढ़ आई थी। वैज्ञानिक अध्ययनों ने चीन-नेपाल सीमा क्षेत्र में ग्लेशियल झीलों के बढ़ते खतरे को पहले ही रेखांकित किया है। एक अध्ययन में 28 अत्यधिक संवेदनशील ग्लेशियल झीलों की पहचान की गई और अनुमान लगाया गया कि चरम स्थिति में हजारों इमारतें, दर्जनों पुल, जलविद्युत परियोजनाएं और सड़कें प्रभावित हो सकती हैं। यही सबसे कठिन और संवेदनशील प्रश्न है। यह कहना कि चीन को इस आपदा की पहले से पूरी जानकारी थी और उसने जानबूझकर नेपाल को तबाह होने दिया- बिना ठोस प्रमाण के एक गंभीर आरोप होगा। अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रमाण इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब किसी नदी का उद्गम या उसका ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र एक देश में और आबादी वाला निचला हिस्सा दूसरे देश में हो, तब उपग्रह निगरानी, ग्लेशियल झीलों की स्थिति, जलस्तर और भूस्खलन की सूचना साझा करना केवल सद्भावना का विषय नहीं बल्कि मानवीय जिम्मेदारी का विषय होना चाहिए। वैज्ञानिक शोध भी चीन-नेपाल सीमा के ग्लेशियल बेसिनों में क्रॉस-बॉर्डर अर्ली वार्निंग सिस्टम और संयुक्त आपदा प्रबंधन की जरूरत पर जोर देता है। इसलिए चीन से नेपाल को स्पष्ट जवाब मांगना चाहिए- क्या ऊपरी क्षेत्र में किसी असामान्य ग्लेशियल गतिविधि, झील के आकार में बदलाव, भूस्खलन या नदी अवरोध की जानकारी उपलब्ध थी? यदि थी, तो नेपाल को कब और किस माध्यम से चेतावनी दी गई? यह सवाल राजनीतिक आरोप की बजाय वैज्ञानिक पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही के रूप में पूछा जाना चाहिए।

पहला कदम होना चाहिए- राष्ट्रीय ग्लेशियल डिजास्टर मॉनिटरिंग सिस्टम। नेपाल को चीन और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर सीमा क्षेत्र की प्रत्येक संवेदनशील ग्लेशियल झील की नियमित उपग्रह निगरानी करनी चाहिए। जहां खतरा अधिक हो, वहां सेंसर, कैमरा, जलस्तर मापक और सायरन आधारित चेतावनी तंत्र लगाया जाना चाहिए।

दूसरा, नदियों के किनारे बेतरतीब निर्माण रोकना होगा। जलविद्युत परियोजना, पुल, सड़क, होटल और बस्तियों के निर्माण में केवल आर्थिक लाभ नहीं बल्कि आपदा जोखिम मानचित्र को आधार बनाना होगा।

तीसरा, स्थानीय लोगों को केवल आपदा आने के बाद राहत देने की नीति से बाहर निकलना होगा। हर संवेदनशील गांव में नियमित मॉक ड्रिल, सुरक्षित ऊंचे स्थान, निकासी मार्ग और सामुदायिक आपदा दल होने चाहिए।

चौथा, नेपाल-चीन के बीच रियल-टाइम डेटा शेयरिंग समझौता होना चाहिए। किसी ग्लेशियल झील में असामान्य परिवर्तन दिखे तो उसकी सूचना कुछ घंटों में नहीं, कुछ मिनटों में नीचे के क्षेत्रों तक पहुंचे।

भारत के लिए यह खतरा और गंभीर है। नेपाल से निकलने वाली नदियां बिहार में प्रवेश करती हैं। इसलिए भारत को नेपाल में होने वाली प्रत्येक बड़ी हिमालयी घटना को संभावित सीमा-पार आपदा मानना चाहिए।

भारत को नेपाल के साथ मिलकर रियल-टाइम फ्लड अर्ली वार्निंग नेटवर्क बनाना चाहिए। बिहार के सीमावर्ती जिलों में सायरन, मोबाइल अलर्ट, पंचायत-स्तरीय चेतावनी केंद्र और नदी जलस्तर निगरानी प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

भारतीय मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार आपदा प्रबंधन विभाग को नेपाल से मिलने वाले आंकड़ों को एकीकृत करना चाहिए। विशेष रूप से गंडक और कोसी जैसी नदियों के लिए ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में होने वाली असामान्य घटनाओं की सूचना तत्काल निचले इलाकों तक पहुंचनी चाहिए।

भारत को अपने स्तर पर भी उपग्रहों और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हिमालयी क्षेत्र की निगरानी बढ़ानी होगी। साथ ही सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को हेलीकॉप्टर आधारित त्वरित बचाव की संयुक्त योजना तैयार रखनी चाहिए।

आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि यह आपदा प्राकृतिक थी या मानवीय चूक का परिणाम। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अगली आपदा आने से पहले हम तैयार होंगे?

नेपाल को 1978 से लेकर 1993, 2008, 2017, 2025 और 2026 तक की आपदाओं को अलग-अलग घटनाओं के रूप में नहीं बल्कि एक लंबी चेतावनी श्रृंखला के रूप में देखना होगा। हिमालय तेजी से बदल रहा है और जलवायु परिवर्तन ग्लेशियरों तथा हिमनद झीलों के जोखिम को बढ़ा रहा है।

चीन को भी समझना होगा कि तिब्बत की नदियां केवल चीन की भौगोलिक संपत्ति नहीं हैं; उनका पानी नेपाल और भारत की करोड़ों आबादी के जीवन से जुड़ा है। पारदर्शी सूचना-साझाकरण किसी देश पर एहसान नहीं बल्कि सीमा पार मानवीय सुरक्षा की अनिवार्यता है। और भारत को भी यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि नेपाल में आने वाली बाढ़ नेपाल की सीमा पर रुक जायेगी।

हिमालय की नदियां राजनीति से बड़ी हैं। उनका पानी सीमा नहीं देखता, इसलिए आपदा प्रबंधन भी सीमा में बंधा नहीं रह सकता। अब समय है कि नेपाल, चीन और भारत आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर एक साझा हिमालयी आपदा चेतावनी तंत्र बनाएं। क्योंकि अगली बार चेतावनी के लिए हमारे पास शायद कुछ मिनट भी न हों।

रिश्तों की पवित्रता और सुरक्षा के संकल्प का पर्व रक्षाबंधन

योगेश कुमार गोयल

रक्षाबंधन पर्व रक्षा के तात्पर्य से बांधने वाला ऐसा सूत्र है, जिसमें बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर जीवन के हर संघर्ष तथा मोर्चे पर उनके सफल होने तथा निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर रहने की ईश्वर से प्रार्थना करती हैं तथा उनके सुखद जीवन के लिए मंगलकामना करती हैं। भाई इस कच्चे धागे के बदले अपनी बहनों की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं और उनके शील एवं मर्यादा की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। वास्तव में भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन स्नेह, सौहार्द एवं सद्भावना का एक ऐसा पर्व है, जो उन्हें अटूट एकता के सूत्र में बांध देता है।

श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन पर्व की भारतीय समाज और संस्कृति में कितनी महत्ता है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बहनों के हाथ अपने भाइयों की कलाईयों पर राखियां बांधने के लिए मचल उठते हैं और कलाई पर बांधे जाने वाले मामूली से दिखने वाले इन्हीं कच्चे धागों से पक्के रिश्ते बनते हैं। पवित्रता तथा स्नेह का सूचक यह पर्व भाई-बहन को पवित्र स्नेह के बंधन में बांधने का पवित्र एवं यादगार दिवस है। इस पर्व को भारत के कई हिस्सों में श्रावणी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में 'गुरु महापूर्णिमा', दक्षिण भारत में 'नारियल पूर्णिमा' तथा नेपाल में इसे 'जनेऊ पूर्णिमा' के नाम से जाना जाता है।

रक्षाबंधन मनाए जाने के संबंध में अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब देवराज इन्द्र बार-बार राक्षसों से परास्त होते रहे और हर बार राक्षसों के हाथों देवताओं की हार से निराश हो गए तो इन्द्राणी ने बहुत कठिन तपस्या की और अपने तपोबल से एक रक्षासूत्र तैयार किया। यह रक्षासूत्र इन्द्राणी ने

देवराज इन्द्र की कलाई पर बांध दिया। तपोबल से युक्त इस रक्षासूत्र के प्रभाव से देवराज इन्द्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हुए। तभी से रक्षाबंधन पर्व की शुरूआत हुई। एक उल्लेख यह भी मिलता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, तब उन्होंने एक ब्राह्मण वेश धारण कर अपनी दानशील प्रवृत्ति के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध राजा बलि से तीन पग भूमि दान में मांगी और बलि द्वारा उनकी मांग स्वीकार कर लिए जाने पर भगवान वामन ने अपने पग से सम्पूर्ण पृथ्वी को नापते हुए बलि को पाताल लोक भेज दिया। कहा जाता है कि उसी की याद में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया।

रक्षाबंधन पर्व से कई ऐतिहासिक प्रसंग भी जुड़े हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस पर्व की शुरूआत मध्यकालीन युग से मानी जाती है। भारतीय इतिहास ऐसे प्रसंगों से भरा पड़ा है, जब राजपूत योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनके देश की बेटियां उन वीर सैनिकों की आरती उतारकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करती थी तथा वीर रस के गीत गाकर उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनसे राष्ट्र की रक्षा का प्रण भी कराती थी। कहा जाता है कि उस जमाने में अधिकांश मुस्लिम शासक हिन्दू युवतियों का बलपूर्वक अपहरण करके उन्हें अपने हरम की शोभा बनाने का प्रयास किया करते थे और ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए राजपूत कन्याओं ने बलशाली राजाओं को राखियां भेजकर उनके साथ भ्रातृत्व संबंध स्थापित कर अपने शील की रक्षा करनी आरंभ कर दी थी। उसी परम्परा ने बाद में रक्षाबंधन पर्व का रूप ले लिया।

चितौड़ की महारानी कर्मावती का प्रसंग तो इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जब गुजरात के शासक बहादुरशाह ने चितौड़ पर आक्रमण कर दिया तो चितौड़ की महारानी कर्मावती घबरा गई। उन्हें चितौड़ के साथ-साथ स्वयं की तथा चितौड़ की अन्य राजपूत बालाओं की सुरक्षा का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कोई उपाय न सूझने पर रानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं को राखी के धागे में रक्षा का पैगाम भेजा और हुमायूं को अपना भाई मानते हुए उनसे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की।

बादशाह हुमायूं महारानी कर्मावती का यह रक्षासूत्र और संदेश पाकर भाव विभोर हो गए और अपनी इस अनदेखी बहन के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाने तुरन्त अपनी विशाल सेना लेकर चितौड़ की ओर रवाना हो गए लेकिन जब तक वह चितौड़ पहुंचे, तब तक महारानी कर्मावती और चितौड़ की हजारों वीरांगनाएं अपने शील की रक्षा हेतु अपने शरीर की अग्नि में आहूति दे चुकी थी। उसके बाद हुमायूं ने महारानी कर्मावती की चिता की राख से अपने माथे पर तिलक लगाकर बहन के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने के लिए जो कुछ किया, वह इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया तथा इसी के साथ रक्षाबंधन पर्व के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय भी जुड़ गया। इस ऐतिहासिक घटना के बाद ही यह परम्परा बनी कि कोई भी महिला या युवती जब किसी व्यक्ति को राखी बांधती है तो वह व्यक्ति उसका भाई माना जाता है।

समय के साथ-साथ रक्षाबंधन पर्व के स्वरूप और मूल उद्देश्य में बहुत बदलाव आया है। तेजी से आधुनिकता की ओर अग्रसर आज के इस भागदौड़ भरे और स्वार्थपरक जमाने में जहां बहनों के लिए अब राखी का अर्थ भाई से महंगे उपहार तथा नकदी इत्यादि पाना हो गया है, वहीं भाई भी अपनी निजी जिन्दगी की व्यस्तताओं के चलते बहनों के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाते। ऐसे में यह पवित्र पर्व अब रुपये-पैसे तथा साड़ी, आभूषण व अन्य कीमती उपहारों इत्यादि के लेन-देन का पर्व बनता जा रहा है और भाई-बहन के बीच राखी का मोलभाव होने की वजह से धीरे-धीरे इस पर्व की मूल भावनाएं सिकुड़ रही हैं। कच्चे धागों की जगह रेशम के धागों ने ले ली और अब इन धागों की अहमियत कम होती जा रही है।

रक्षाबंधन महज कलाई पर एक धागा बांधने की रस्म नहीं है बल्कि यह भाई-बहन के अटूट स्नेह, पवित्रता और सद्भावना का पर्व है। यह पर्व रिश्तों की पवित्रता और वचनबद्धता का प्रतीक है। इसलिए रक्षाबंधन पर्व को चंद रुपयों या कीमती उपहारों से तोलकर देखना इस पर्व के अंतस में विद्यमान पवित्र भावना का अपमान है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

कचरे के ढेर, बीमारियों के शहर

हम अपने घर को साफ रखने के महत्व से अवगत हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमारी जिम्मेदारी की भावना गायब हो जाती है। कई लोगों को घरेलू सामान सड़क के किनारे, नाले में, खाली जगह पर या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने की आदत पड़ गई है। प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन, सब्जियों के छिलके, फलों के अवशेष और बचा हुआ खाना नियमित रूप से खुले में फेंक दिया जाता है। लेकिन लापरवाही का यह मामूली सा काम धीरे-धीरे लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन रहा है।

खुले में कूड़ा फेंकने से वह सड़ने लगता है और दुर्गंध आने लगती है। समस्या केवल 'असुविधा' की नहीं है। कचरे के जमाव से गंदगी फैलती है और मक्खियाँ, मच्छर, आवारा जानवर और अन्य कीट आकर्षित होते हैं। प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थ नालियों को जाम कर सकते हैं जिससे बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाता है। पानी के बहाव में कमी से मच्छरों के पनपने के स्थान बन जाते हैं और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यदि कोई एक व्यक्ति लापरवाही बरतता रहता है, तो यह पूरे मोहल्ले के लिए स्वास्थ्य समस्या बन सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि समाज के लोग इसे एक सामान्य बात समझने लगे हैं। हम सड़क किनारे कचरे के ढेर देखते हैं, कुछ पल के लिए नाक ढक लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत कम लोग सोचते हैं कि यह कचरा कहाँ से आता है। वास्तव में, हर कचरे के पीछे किसी न किसी की सुविधा और लापरवाही होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कभी कचरा नहीं डालता, तो वह उसे घर के बाहर कूड़ेदान में क्यों नहीं डालता? जब हम अपने घरों से दूर होते हैं तो सड़कें कूड़ेदान क्यों बन जाती हैं? यह सिर्फ स्वच्छता से कहीं बढ़कर है – यह नागरिक कर्तव्य और सामाजिक आचरण का मामला है। प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। अगर इसे यूं ही फेंक दिया जाए, तो यह नालियों को जाम कर सकता है और पानी के बहाव को रोक सकता है। प्लास्टिक की थैलियों में बचा जैविक कचरा सड़ता रहता है और दुर्गंध फैलाता है, जिससे अस्वच्छता पैदा होती है। आवारा जानवर भी प्लास्टिक खा सकते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसलिए, प्लास्टिक का अंधाधुंध और लापरवाही से निपटान समाज, जानवरों और पर्यावरण को प्रदूषित करता है।

कचरे और बीमारियों के बीच संबंध में धारणा और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं है। खुले कूड़ेदानों में मक्खियाँ और अन्य परजीवी जमा हो जाते हैं, जो बीमारियाँ फैलाते हैं। जमा हुआ और ठहरा हुआ पानी मच्छरों के प्रजनन का स्थान बन सकता है। अनियंत्रित कचरे से कम दूरी पर स्थित घरों में संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक हो सकता है। इस मानसून के मौसम में स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि बारिश के मौसम में कचरा और दूषित पदार्थ आसपास के इलाकों में फैल सकते हैं। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि समस्या केवल नगरपालिकाओं की है। स्थानीय सरकारें समुदाय को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं: कूड़ा संग्रहण, अपशिष्ट निपटान, नालियों का रखरखाव और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता। साथ ही, इस प्रक्रिया में नागरिकों की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें अपशिष्ट निपटान करते समय ज़िम्मेदार होना चाहिए, कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, प्लास्टिक का अनावश्यक उपयोग सीमित करना चाहिए और गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करना चाहिए। हालांकि, अगर निवासी सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकते रहेंगे तो अधिक सफाई कर्मचारियों की तैनाती से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। अब जरूरत इस बात की है कि स्वच्छता को सरकारी अभियान के रूप में न लिया जाए। स्वच्छता अभियानों की प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से दैनिक जीवन में स्वच्छता को शामिल करने से जुड़ी है। बच्चों को स्कूलों में स्वच्छता पर भाषण देखने चाहिए, साथ ही उन्हें स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई व्यावहारिक उपाय भी अपनाने चाहिए, जिनमें कचरे का पृथक्करण, कचरे का उचित निपटान और एकल-उपयोग प्लास्टिक का कम से कम उपयोग शामिल है।

बाहर काम कर रहे बंगाल के कुशल पेशेवर राज्य लौटें: शुभेंदु

कोलकाता, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बृहस्पतिवार को देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में काम कर रहे राज्य के कुशल और शिक्षित पेशेवरों से वापस लौटने की अपील की और उन्हें डबल इंजन सरकार के तहत अवसर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

न्यू टाउन में एलटीएम के नए आईटी कैंपस 'आनंद निकेतन' के पहले चरण के उद्घाटन के अवसर पर शुभेंदु ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता राज्य के बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और पश्चिम बंगाल को फिर से निवेश के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। उन्हें नौकरियों की जरूरत है और वे बंगाल में काम करने के लिए काफी इच्छुक हैं। मुख्यमंत्री ने लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) समूह का हिस्सा एलटीएम को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कंपनी को अतिरिक्त 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने बताया कि कंपनी ने करीब दो महीने पहले सरकार को पत्र लिखकर जमीन की मांग की थी।

एलटीएम के आनंद निकेतन आईटी कैंपस के पहले चरण में करीब आठ लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैली दो इमारतें शामिल हैं।

प्याज की कीमतों में उछाल के लिए बिचौलियों की मुनाफाखोरी जिम्मेदार: चौहान

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए बिचौलियों को जिम्मेदार ठहराया और इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को उचित लाभ मिले और ग्राहकों पर ऊंची कीमतों का असर न पड़े। राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंचने के बीच सरकार ने बफर स्टॉक जारी किया है। वहीं चौहान ने कृषि बाजार व्यवस्था में बिचौलियों की भूमिका की आलोचना की है।

मंत्री ने याद दिलाया कि कुछ महीने पहले केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा था और महाराष्ट्र में किसानों से प्याज खरीदना पड़ा था क्योंकि कीमतें गिरकर 7-8 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गई थीं, जो उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए काफी नहीं थीं।

अब, किसानों के पास प्याज नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना स्टॉक बेच दिया है और खुदरा कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। चौहान ने राजधानी में एक उद्योग कार्यक्रम में कहा, क्या किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलता है? क्या बिचौलियों को इतना मुनाफा कमाने का हक है? सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है।

मंत्री ने उद्योग से एक ऐसी व्यवस्था बनाने में मदद मांगी जिससे यह पक्का हो सके कि किसानों को मुनाफा मिले और ग्राहकों को भी ज्यादा कीमत न चुकानी पड़े।

चौहान ने कहा, हमें कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए एक टीम भी बनाई गई है। मंत्री ने कृषि मूल्य श्रृंखला में किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।

टिकाऊ विकास के लिए सीआईआई-आईटीसी उत्कृष्टता केंद्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने खाद्य सुरक्षा को पक्का करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव और रूस-यूक्रेन युद्ध को देखते हुए भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रह सकता।

मंत्री ने रसायन और उर्वरक के संतुलित इस्तेमाल, पानी के सही इस्तेमाल, एकीकृत खेती और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने, और जलवायु-स्मार्ट कृषि को अपनाने के जरिये मिट्टी की सेहत सुधारने की जरूरत के बारे में बात की।

चौहान ने आधुनिक प्रौद्योगिकी और शोध के काम को किसानों के खेतों तक ले जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों को सलाह दी गई है कि वे किसानों के खेतों में जाकर समस्याओं का पता लगाएं और फिर शोध कार्यक्रम शुरू करें। मंत्री ने उद्योग से कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बनाने में निवेश करने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कोष का इस्तेमाल क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए।

देश में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं : गहलोत

जयपुर, एजेंसी।

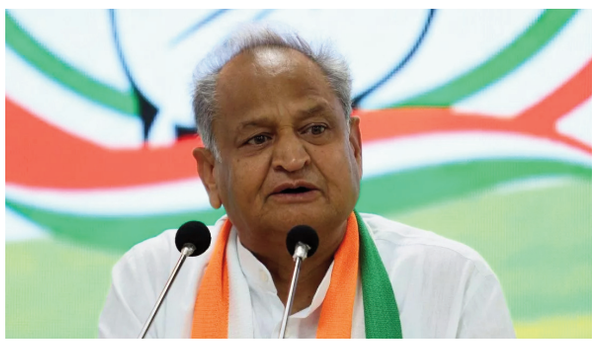

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को इसकी कार्यशैली पर गंभीरता से विचार करना होगा। गहलोत ने एक बयान में आयोग पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया, जिस भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता की मिसाल कभी पूरी दुनिया देती थी, आज उसकी यह दुर्गति हो गई कि वह सत्ताधारी दल के पक्ष में काम करता नजर आ रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यही वह आयोग है जिसने नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया समेत कई देशों के चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया, जो 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फोर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन असिस्टेंस' का संस्थापक सदस्य रहा और जिसकी साख पर दुनिया भरोसा करती थी।

उन्होंने दावा किया कि आज उसी आयोग की कार्यशैली पर देश में ही सवाल खड़े हो गए हैं।

गहलोत ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में इसकी गंभीर बानगी सामने आई है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अपीलीय न्यायाधिकरण ने अब तक जिन 82,782 अपीलों पर सुनवाई पूरी की, उनमें से 91 प्रतिशत मामलों में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे जाने की बात सामने आई है।

कांग्रेस नेता ने कहा, ''सवाल यह है कि बंगाल में करीब 27 लाख वोट काटे जाने की शिकायतें हैं, अभी तक इसका महज एक छोटा हिस्सा ही निपटा है, तो बाकी लाखों अपीलों का क्या होगा?''

गहलोत के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार 'वोट चोरी' का मुद्दा जिस मजबूती से उठाते रहे हैं, यह आंकड़े उस पर मुहर लगा रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''सबसे दुखद यह है कि न्यायपालिका भी इस पर आंखें मूंदे बैठी है। चुनाव के दौरान एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी कि जो लोग एसआईआर की वजह से इस बार वोट नहीं दे पा रहे, वे अगली बार वोट दे लेंगे। गहलोत ने कहा कि अब देश को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीरता से विचार करना होगा, वरना लोकतंत्र की बुनियाद ही खोखली हो जाएगी।

युवाओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार: मुख्यमंत्री शर्मा

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को मेहनत व लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शर्मा ने 'युवा शक्ति' को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'खेलो इंडिया संवाद' कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। युवाओं के धैर्य, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम से ही 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार किया जा सकता है।

त्रिपुरा विधानसभा में मंत्री की माकपा विरोधी टिप्पणियों को लेकर हंगामा हुआ

अगरतला, एजेंसी।

त्रिपुरा विधानसभा में बृहस्पतिवार को उस समय हंगामा हो गया, जब संसदीय कार्य मंत्री रतनलाल नाथ ने माकपा को राष्ट्र-विरोधी और विदेशी एजेंट करार दिया जिसके बाद इस टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल के तुरंत बाद नाथ ने क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सान एगुइलेरा की हालिया त्रिपुरा यात्रा का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय यात्रा के दौरान राजदूत ने किसी राजनीतिक दल के कार्यालय का दौरा नहीं किया, सिवाय माकपा के राज्य मुख्यालय के। नाथ ने कहा कि 21 अगस्त को रवींद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में क्यूबा के राजदूत ने अमेरिका के औपनिवेशिक मानसिकता के लिए उसकी आलोचना की और त्रिपुरा की हरियाली की अपने देश से तुलना की। नाथ ने कहा, कार्यक्रम में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी को भी भारत की औपनिवेशिक मानसिकता पर खेद जताते हुए सुना गया, जबकि भारत ने कभी किसी देश पर कब्जा नहीं किया।

सार समाचार

जम्मू प्रशासन ने चीनी 'मांझा' की बिक्री पर पूर्णत: रोक लगाई

जम्मू,एजेंसी। जम्मू जिला प्रशासन ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों, बच्चों और पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर पतंग उड़ाने में काम आने वाले प्लास्टिक, नायलॉन और चीनी 'मांझा' की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है तथा इसका उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान भी है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राकेश मिन्हास द्वारा जारी आदेश के अनुसार अभी पतंग उड़ाने का मौसम चल रहा है और इसके आने वाले सप्ताहों में भी जारी रहने की संभावना है, जिससे पूरे जम्मू जिले में पतंग उड़ाने के सामान का इस्तेमाल बढ़ गया है। पुख्ता जानकारी मिली है कि सरकारी आदेश एसआरओ-126 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत रोक के बावजूद जम्मू जिले की सीमा के भीतर प्लास्टिक, नायलॉन और अन्य सिंथेटिक 'मांझा' धागे (जिनमें चीनी मांझा और इसी तरह की नॉन-बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक डोर शामिल हैं) बनाए जा रहे हैं, उनका स्टॉक किया जा रहा है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, बिक्री के लिए दिखाया जा रहा है, बेचा और इस्तेमाल किया जा रहा है।

युवाशक्ति परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत: शेखावत

जोधपुर,एजेंसी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने युवाशक्ति को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा है कि यदि युवा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाये तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।

शेखावत ने गुरुवार को यहां खेलो इंडिया डायलॉग-युवा संवाद कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत आज बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस परिवर्तन में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में करीब 65 प्रतिशत आबादी युवा है। ऐसे में यही युवाशक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, उनमें युवाओं की भूमिका रही है।

झारखंड: कांग्रेस ने सभी जिलों में खनिज कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया

रांची, एजेंसी।

कांग्रेस की झारखंड इकाई ने एमएमडीआर अधिनियम के खिलाफ राज्य के सभी 24 जिलों में बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। इस कानून का उद्देश्य खनिज अधिकारों और खनिज वाली भूमि पर कर लगाने के संबंध में राज्यों के अधिकारों को सीमित करना है।

दिनभर धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए और उपायुक्तों के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया। रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से विरोध मार्च निकाला। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी करीब दो किलोमीटर दूर स्थित जिला समाहरणालय पहुंचे, जहां मार्च के बाद धरना दिया गया।

कमलेश ने संवाददाताओं से कहा, ''सभी 24 जिलों के समाहरणालयों में प्रदर्शन आयोजित किए गए।

भाजपा ने जेपी को बेचा: अखिलेश

लखनऊ, एजेंसी। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) के संचालन का जिम्मा एक निजी संचालक को सौंपे जाने को लेकर बृहस्पतिवार को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने जेपी को बेच दिया है।

यादव ने एक रुपया ज्यादा लेकर जेपीएनआईसी को सपा को वापस देने की पेशकश करते हुए घोषणा की कि अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।

बीएचयू में रामायणी सम्मान का भव्य आयोजन

वाराणसी, साहस समाचार।

गोस्वामी तुलसीदास जयंती के पावन अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में 'रामायणी सम्मान' समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह में रामायण, भारतीय संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली देशभर की 28 प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया गया।

सम्मान चयन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए चयन समिति के सदस्य एवं काउंसिल के ट्रस्टी डॉ. भारत नागर ने बताया कि श्रीराम, सीतामाता और रामायण के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों की पहचान के लिए काउंसिल पूरे वर्ष प्रत्येक जिले में विशेष अभियान चलाएगी। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों के योगदान को पहचान, सम्मान और प्रोत्साहन देना है, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें और रामायण के संदेश को व्यापक स्तर पर विश्वभर में पहुंचाया जा सके।

नैनीताल-ऊधम सिंह नगर के सांसद एवं रामायण रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा कि देश में रामायण साहित्य, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय हित के क्षेत्र में अनेक प्रतिभाएं कार्य कर रही हैं। ऐसी प्रतिभाओं को उचित मंच और पहचान देना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना बेहद जरूरी है। युवाओं को सही दिशा और सकारात्मक प्रेरणा देकर उन्हें देश और समाज के लिए उपयोगी कार्यों से जोड़ने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत चतुर्वेदी ने 'रामायणी सम्मान' के आयोजन को गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि रामायण भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का महत्वपूर्ण आधार है तथा इससे जुड़े कार्यों को सम्मानित किया जाना समाज के लिए प्रेरणादायी है।

समारोह में भजन सम्राट एवं पद्मश्री से सम्मानित अनुप जलोटा को भी 'रामायणी सम्मान' प्रदान किया गया। उन्होंने भगवान श्रीराम के प्रति समर्पित भजन प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को भावविभोर कर दिया।

मराठा नेताओं के पास ओबीसी प्रमाण पत्र: वडेट्टीवार

नागपुर, एजेंसी।

महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि सुप्रिया सुले समेत कई वरिष्ठ मराठा नेताओं ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र हासिल कर लिए हैं। हालांकि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले द्वारा दावा साबित करने की चुनौती दिए जाने के बाद उन्होंने अनजाने में उनका नाम लेने पर खेद व्यक्त किया।

महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन 'महा विकास आघाडी' (एमवीए) और राष्ट्रीय स्तर पर 'इंडिया' गठबंधन में कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (एसपी) सहयोगी दल हैं। वडेट्टीवार से ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके के उस आरोप के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के एक मंत्री ने ओबीसी श्रेणी का प्रमाण पत्र हासिल किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वडेट्टीवार ने दावा किया, आधी मराठा आबादी ने ओबीसी श्रेणी का प्रमाण पत्र ले लिया है... लगभग 90 प्रतिशत लोगों ने।

कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता ने आरोप लगाया, (आरक्षण कार्यकर्ता) मनोज जरांगे को शायद यह नहीं मालूम होगा कि सुप्रिया सुले सहित लगभग सभी बड़े (मराठा) नेताओं के पास ओबीसी जाति प्रमाण पत्र है। लगभग हर किसी ने ओबीसी श्रेणी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। अब यह ऐसा हो गया है जैसे ओबीसी सामान्य श्रेणी बन गयी हो और बाकी लोग ओबीसी; हर कोई 27 प्रतिशत ओबीसी कोटे में शामिल होने की कोशिश कर रहा है।

जरांगे मांग कर रहे हैं कि मराठों को 'कुनबी' जाति प्रमाण पत्र दिए जाएं ताकि वे ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा सकें। महाराष्ट्र में खेती-किसानी से जुड़े कुनबी समुदाय को ओबीसी श्रेणी में रखा गया है और उन्हें शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है।

आदिवासी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आईं नेहा बोरा

नागपुर,एजेंसी । ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने नागपुर में प्रदर्शन कर रहे आदिवासी छात्रों को अपना पूरा समर्थन देते हुए छात्रावास सुविधाओं और छात्रों के अधिकारों के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।

नागपुर के वसंतराव देशपांडे हॉल में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए सुश्री बोरा ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी छात्रों की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह विफल रही है।

प्रशांत किशोर ने मुख्य सचिव से की मुलाकात

पटना, एजेंसी।

जन सुराज पार्टी के संस्थापक एवं बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने बृहस्पतिवार को बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात कर अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की।

हालिया विधानसभा उपचुनाव में पहली बार जीत दर्ज करने वाले किशोर ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य की राजधानी के मध्य स्थित बांकीपुर क्षेत्र की अनेक समस्याएं बैठक में उठाई गईं। किशोर ने कहा, आज की बैठक को पिछले सप्ताह पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के साथ हुई मेरी बैठक की अगली कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। आज की बैठक में डीजीपी के अलावा प्रधान सचिव स्तर के पांच अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अगले महीने शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित करने पर भी सहमति बनी है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। जन सुराज प्रमुख ने कहा कि मुख्य सचिव ने यह भी आश्वासन दिया कि लाभुकों को हर महीने निर्धारित पांच किलोग्राम खाद्यान्न नहीं मिलने तथा पेयजल आपूर्ति की कमी से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

मेघालय भारत का सबसे बड़ा जैविक खेती करने वाला राज्य बनने की दिशा में अग्रसर: संगमा

शिलांग, एजेंसी।

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि रासायनिक उर्वरकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की राज्य सरकार की पहल के चलते मेघालय देश में सर्वाधिक ऑर्गेनिक कवरेज वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रश्नकाल के दौरान संगमा ने कहा, हमें यह बड़ा संदेश ध्यान में रखना चाहिए कि मेघालय और पूरी दुनिया ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। हम यहाँ उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने नहीं, बल्कि उसे हतोत्साहित करने के लिए हैं।

उन्होंने कहा, बायो-फर्टिलाइजर (जैविक उर्वरक) लाए गए हैं। हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और उम्मीद है कि एक दिन राज्य रासायनिक उर्वरकों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। फिलहाल हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन (प्रमाणन) की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आज मेघालय इस मामले में काफी मजबूत स्थिति में है। विपक्ष की 'वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी' के विधायक आर्डेंट मिलर बसावमोइट ने आरोप लगाया था कि किसानों को 'सिंगल सुपर फॉस्फेट' 900 रुपये प्रति बोरी खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए संगमा ने स्पष्ट किया कि यूरिया की कीमत 266 रुपये प्रति बोरी है, जबकि 1,200 रुपये बाजार मूल्य वाला एसएसपी 800 रुपये की सब्सिडी दर पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, सीमित आपूर्ति के कारण कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सरकार लगातार निगरानी रख रही है।

खाताधारक 10,000 रुपये तक की 'ओवरड्रॉफ्ट' सुविधा के भी पात्र हैं, जिससे आपात स्थिति में उन्हें वित्तीय सहायता मिलती है

12 साल में जन धन खातों की संख्या 59 करोड़ के पार

नई दिल्ली, एजेंसी।

सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 12 साल पूरे हो गए हैं और इसके तहत खोले गए बैंक खातों की संख्या 59 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय के अनुसार, इन खातों में कुल जमा राशि 3.17 लाख करोड़ रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अगस्त, 2014 को पीएमजेडीवाई की शुरुआत की थी। योजना का उद्देश्य बैंक सुविधाओं से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएं पहुंचाना है। मंत्रालय के अनुसार, पीएमजेडीवाई के 78 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, जबकि करीब 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के नाम हैं।

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि 19 अगस्त, 2026 तक प्रति खाता औसत जमा राशि 5,356 रुपये थी। पिछले 12 वर्षों में प्रति खाता औसत जमा राशि 3.4 गुना बढ़ी है।

मंत्रालय ने कहा कि औसत जमा राशि में वृद्धि खातों के बढ़ते इस्तेमाल और खाताधारकों में बचत की आदत विकसित होने का एक और संकेत है। योजना की वर्षगांठ पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पीएमजेडीवाई की सफलता को केवल खोले गए खातों की संख्या के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि देश के बैंकिंग और वित्तीय परिदृश्य में आए बदलाव के संदर्भ में भी इसका आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएमजेडीवाई ने लाखों लोगों, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद की है।

चौधरी ने कहा, खाते के स्वामित्व ने आम आदमी के लिए बीमा और पेंशन कवरेज हासिल करना संभव बनाया है। प्रत्येक राज्य और जिले में लगातार चलाए गए 'संतृप्ति' अभियान के माध्यम से हम बैंक खातों की लगभग सार्वभौमिक पहुंच की दिशा में आगे बढ़े हैं और जरूरतमंद लोगों तक बीमा तथा पेंशन योजनाओं की पहुंच लगातार बढ़ाई गई है।

उन्होंने पीएमजेडीवाई को आम लोगों तक पहुंचाने और इसकी सफलता में योगदान देने के लिए देशभर में तैनात बैंकरों तथा बैंकिंग प्रतिनिधियों के प्रयासों की भी सराहना की।

मंत्रालय ने कहा कि पीएमजेडीवाई को केंद्र में रखकर बनाई गई जन-धन, आधार और मोबाइल (जेएएम) त्रिमूर्ति वित्तीय सहायता के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए एक ऐसा तंत्र साबित हुई है, जिसमें धन के दुरुपयोग की गुंजाइश बेहद कम है।

मंत्रालय के अनुसार, जेएएम के जरिये सरकार ने वंचित वर्गों के बैंक खातों में कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सीधे अंतरित किए हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका और भुगतान में होने वाली देरी को खत्म करने में मदद मिली है।

पीएमजेडीवाई के तहत पात्र खाताधारकों को बिना न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता और रखरखाव शुल्क के मूल बैंक खाता उपलब्ध कराया जाता है। इन खातों के साथ मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड भी दिए जाते हैं, जिन पर दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।

मंत्रालय ने कहा कि पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 41.29 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं और समय के साथ इन कार्ड की संख्या तथा उनका इस्तेमाल बढ़ा है। खाताधारक 10,000 रुपये तक की 'ओवरड्रॉफ्ट' सुविधा के भी पात्र हैं, जिससे आपात स्थिति में उन्हें वित्तीय सहायता मिलती है।

सार समाचार

दूध से लेकर शराब तक, केरल ओणम की भावना में डूबा

तिरुवनंतपुरम,एजेंसी। यदि ओणम प्रकृति की उदारता का उत्सव है, तो केरल ने इस बात को अक्षरशः अपनाया है, क्योंकि यहां दूध की भरपूर मात्रा बह रही है और शराब भी कम नहीं है। मिल्मा ने 20 अगस्त से 25 अगस्त को उथरादम (पहला ओणम) तक 1.46 करोड़ लीटर दूध बेचकर दूध की बिक्री में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। दही की बिक्री तो और भी बेहतर रही, इसी अवधि में 9.68 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18 लाख किलोग्राम से अधिक की बिक्री हुई। उथरादम से पहले के आठ दिनों में बीईवीसीओ और कंज्यूमरफेड के माध्यम से शराब की बिक्री बढ़कर 771.29 करोड़ रुपए हो गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 694.96 करोड़ रुपए थी, यानी लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि। उथरादम का दिन केरल के शराब विक्रेताओं के लिए विशेष रूप से व्यस्त रहा।

दरभंगा में बाढ़ का खतरा नहीं : समाहर्ता

दरभंगा,एजेंसी। नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में ग्लेशियर झील फटने के बाद नदियों में तेज प्रवाह तथा बिहार के कुछ हिस्सों में संभावित बाढ़ की स्थिति के बीच दरभंगा जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है और सभी नदियां खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही हैं।अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) सलीम अख्तर ने कहा कि ग्लेशियर झील फटने का प्रभाव गंडक नदी से जुड़े कुछ जिलों में होने की बात सामने आई है, लेकिन दरभंगा में इसका कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क और सचेत रहने की अपील की।

अख्तर ने बताया कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर के कुछ हिस्से तथा वैशाली के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ने की बात सामने आई है, जबकि दरभंगा फिलहाल इससे अछूता है।

रक्षा आधुनिकीकरण आत्मनिर्भर भारत-सशक्त सेना और नए भारत के पराक्रम का प्रतीक : यादव

भोपाल, एजेंसी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश को मिली बड़ी सौगात के बाद अब जबलपुर में आरंभ हो रही ₹टी-सीरीज टैंक ओव्हरहॉल परियोजना₹ देश की रक्षा क्षमता को और मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना सिर्फ रक्षा आधुनिकीकरण नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत, सशक्त सेना और नए भारत के पराक्रम का प्रतीक भी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री में टी सीरिज टैंक ओव्हरहॉल परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के सतत प्रयासों से भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रक्षामंत्री सिंह का संकल्प वज्र के समान अडिग है। उनके नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर दुनिया को नए भारत की शक्ति और पराक्रम का परिचय दिया है। रक्षामंत्री सिंह केवल लक्ष्य तय नहीं करते, बल्कि उन्हें हासिल करने का विश्वास भी देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले जबलपुर की धरती से बॉर्डर की रक्षा के लिए नए प्रकल्प की शुरुआत हो रही है। आज जबलपुर को लगभग 475 करोड़ से अधिक लागत की नई परियोजना की सौगात मिली है। टी-सीरीज टैंक के ओव्हरहॉल प्रोजेक्ट के माध्यम से भारतीय सेना नए दौर में प्रवेश कर रही है। जबलपुर की आर्मर्ड फैक्ट्री ने अपने काम के बल पर देशभर में विशेष पहचान बनाई है। भविष्य में आने वाली चुनौतियों के चलते सेना को मजबूत बनाने के लिए मध्य प्रदेश स्थित अलग-अलग फैक्ट्रियों से उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को लगातार रक्षा क्षेत्र में नई सौगातें मिल रही हैं। भोपाल में बीईएमएल के माध्यम से महत्वपूर्ण परियोजना मिली है। प्रदेश में वंदे भारत सहित विभिन्न प्रकार के कोचों के निर्माण की दिशा में भी काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निवेश से मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को गति देना है। हाल ही में मालनपुर में लगभग 450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली गोदरेज फैक्ट्री का लोकार्पण किया गया है। अब रक्षा क्षेत्र में पौने पांच सौ करोड़ रुपये की परियोजना की सौगात मिली है। इससे प्रदेश में निवेश की नई संभावनाएं बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश शिक्षा, चिकित्सा, अधोसंरचना और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश से 74 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होना इस प्रगति का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मध्य प्रदेश भविष्य के विकसित भारत के निर्माण में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार औद्योगीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश की गंगा बह रही है, जो हमारे लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलेगी। कल ही मालनपुर, भिंड में गोदरेज समूह के कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मध्य प्रदेश शिक्षा, रोजगार, निवेश सहित हर क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश का विदेशी निर्यात बहुत बढ़ा है।

बातचीत और हड़ताल साथ-साथ नहीं चल सकते: मुख्यमंत्री मान

चंडीगढ़, एजेंसी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर कहा है कि बातचीत और हड़ताल साथ-साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बातचीत तभी होगी जब हड़ताल खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, कर्मचारी हमारे परिवार का अहम हिस्सा हैं और हम उनकी हर जायज बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत और हड़ताल साथ-साथ नहीं चल सकते। सरकार हर मुद्दे का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बातचीत तभी होगी जब हड़ताल खत्म हो जाएगी।

उधर, राज्यभर में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशनील कुमार शर्मा ने कहा, आज हम डीसी कार्यालय में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यह प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। अगर पंजाब सरकार ने हमें शांति से, प्यार और सम्मान के साथ विरोध करने का मौका दिया होता, तो हमारे लिए अपना सरकारी काम छोड़कर सड़कों पर उतरने की कोई वजह नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमारे साथ 15 से 20 जत्थेबंदियां शामिल हैं। अशनील शर्मा ने कहा कि यह हमारा एक दिन का अवकाश लेने वाला प्रदर्शन था। शाम को बैठक की जाएगी। आगे जो भी निर्णय लिया जाता है, उसे लागू किया जाएगा।

अशनील कुमार शर्मा ने कहा कि हमारी पहली मांग महंगाई भत्ते (डीए) की है, जो हमारा कम है। इसके लिए हमें कोर्ट भी जाना पड़ा था। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भी मिलनी चाहिए। यह हमारी बिल्कुल जायज मांगें हैं।

हमारा सरकार से अनुरोध है कि यह हमारी जायज मांगें हैं, इनको मान लिया जाना चाहिए। अमृतसर में बात करते हुए जूनियर इंजीनियर्स काउंसिल सिटी सर्कल के अध्यक्ष के राम कुमार ने कहा, आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। पूरे पंजाब में सभी सरकारी कर्मचारी आज सामूहिक छुट्टी पर हैं। जेई काउंसिल ड्यूटी पर मौजूद है। हमारे बोर्ड और अन्य संगठन के विरोध करने का अपना अलग तरीका है।

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता पर व्यापक मंथन

रायपुर, एजेंसी।

समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस द्वय शत्रुघ्न सिंह और एम.के.राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार, सेवानिवृत्त ज्योति रानी सिंह और सदस्य सचिव श्याम धावड़े के समक्ष आज गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में धार्मिक और सामाजिक संगठनों सहित आयोग, निगम, मंडल के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर समान नागरिक संहिता के संबंध में सुझाव लिए गए।

संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को साकार करने के उद्देश्य से गठित यूसीसी समिति के समक्ष धार्मिक और सामाजिक संगठनों तथा विभिन्न वर्गों सहित आयोग, निगम, मंडल के पदाधिकारियों की सहभागिता लगातार देखने को मिल रही है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या पंथ से परे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे पारिवारिक मामलों में एक समान नियम बनाना है। पुत्र और पुत्री दोनों को संपत्ति में समान उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया है। इसके तहत मौखिक तलाक और कुछ अन्य धार्मिक कुप्रथाओं पर रोक लगाई जा सकेगी।

बिहार में टीआरई-4 परीक्षा एकल चरण में होगी

पटना,एजेंसी। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच गुरुवार को हुई वार्ता के बाद कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनी। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में छात्र प्रतिनिधिमंडल की सभी लिखित मांगों पर बिंदुवार चर्चा की गई। बैठक के बाद छात्रों ने सर्वसम्मति से आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 को लेकर हुआ। सरकार ने छात्रों की एकल परीक्षा आयोजित करने की मांग स्वीकार कर ली है।

सरकार ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा की पारदर्शिता से जांच, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के समयबद्ध आयोजन, 1,799 दरोगा पदों की भर्ती परीक्षा की जांच तथा सहायक प्राध्यापक नियुक्ति से पहले बिहार पात्रता परीक्षा आयोजित करने की मांग पर भी निर्णय लिया।

कर्मचारियों को हक देने के बजाय धमकाना बंद करे सरकार: रंधावा

चंडीगढ़,एजेंसी।

पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका लंबित महंगाई भत्ता (डीए) देने में आनाकानी करने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

रंधावा ने कहा कि जब कर्मचारियों की मांगें उनके कानूनी अधिकारों से जुड़ी हैं और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय भी इस संबंध में आदेश दे चुका है, तो सरकार को टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय अदालत के आदेशों का पालन करना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों से बातचीत करने के बजाय सरकार उन्हें डराने-धमकाने की नीति अपना रही है, जिसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। जिन्होंने अपना पूरा जीवन राज्य की सेवा में लगाया, उन्हें अपने जायज अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ संघर्ष करने को मजबूर करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

रंधावा ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी वित्तीय कुप्रबंधन की जिम्मेदारी कर्मचारियों पर डालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्य राज्यों में राजनीतिक प्रचार और पार्टी गतिविधियों पर सरकारी संसाधन खर्च किये जा सकते हैं, तो पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनरों के जायज बकाये के भुगतान के लिए खजाना खाली होने की बात क्यों कही जा रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सत्ता के अहंकार को छोड़कर कर्मचारियों से संवाद करने, अदालत के आदेशों का सम्मान करने और उनके लंबित वैध बकाये तत्काल जारी करने की मांग की। रंधावा ने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों और पेंशनरों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी आवाज दबाने नहीं देगी।

मुख्यमंत्री साय ने जशपुर एक्सप्रेस योजना का किया शुभारंभ

रायपुर/जशपुर, एजेंसी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गुरुवार को बगिया कैम्प कार्यालय में महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 'जशपुर एक्सप्रेस' योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले की 50 महिलाओं को ई-रिक्शा प्रदान कर उन्हें आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई राह से जोड़ा।

रक्षाबंधन के आत्मीय वातावरण में स्व-सहायता समूहों की दीदियों ने मुख्यमंत्री साय की कलाई पर राखी बांधी और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने भी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें साड़ी और मिठाई उपहार स्वरूप भेंट की। बहनों के बीच मुख्यमंत्री का आत्मीय अंदाज कार्यक्रम को विशेष बना गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना सशक्त परिवार और समृद्ध समाज की बुनियाद है। हमारी बहनें आज स्व-सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुड़कर स्वावलंबन की नई इबारत लिख रही हैं। ई-रिक्शा उनके लिए केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि नियमित आय और सम्मानजनक स्वरोजगार का माध्यम बनेगा।

'जशपुर एक्सप्रेस' योजना के माध्यम से महिलाओं को ई-रिक्शा उपलब्ध कराकर उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इससे एक ओर महिलाओं को नियमित आमदनी का माध्यम मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीयस्तर पर आवागमन की सुविधा भी बेहतर होगी।

मुख्यमंत्री साय ने ई-रिक्शा प्राप्त करने वाली बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपने परिश्रम से आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम करें।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने बगिया क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात भी दी। उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से बगिया में बनने वाले विश्राम गृह का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही बगिया में यादव मोहल्ला तक बनने वाली सीसी सड़क के निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया।

जबलपुर : महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

जबलपुर, एजेंसी। बढ़ती महंगाई के विरोध में मौलाना अबुल कलाम आजाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को कोतवाली थाने के बाहर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशन और जिला कांग्रेस कमेटी (शहर) जबलपुर अध्यक्ष सौरभ शर्मा के आह्वान पर आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शक्कर की बढ़ती कीमतों, ई20 पेट्रोल, बढ़ती ईंधन कीमतों, बिजली बिलों और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार में खरीदारी करने पहुंचे आम लोगों और महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से एक चुटकी शक्कर बांटी। इसके जरिए बढ़ती कीमतों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए महंगाई के खिलाफ जनजागरण का प्रयास किया गया।

अपराध के खिलाफ सरकार की नीति स्पष्ट, कानून से बड़ा कोई नहीं: सैनी

चंडीगढ़, एजेंसी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने मिर्चपुर कांड, रोहतक के अपना घर मामले, मानेसर मारुति हिंसा और भगाणा कांड का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस आज सामाजिक न्याय और महिला सुरक्षा की बातें करती है, लेकिन उसके शासनकाल की घटनाएं उसकी संवेदनहीनता की गवाही देती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 अप्रैल 2010 को हिसार के मिर्चपुर गांव में दलित बस्ती पर हमला हुआ था।

घरों में आग लगाई गई और 70 वर्षीय ताराचंद तथा उनकी दिव्यांग बेटी सुमन को जिंदा जला दिया गया। सैकड़ों दलित परिवारों को गांव छोड़ना पड़ा और मामले की सुनवाई हरियाणा से बाहर दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी। उन्होंने मई 2012 के रोहतक के 'अपना घर' कांड का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त आश्रय-गृह में रहने वाली अनाथ, बेसहारा और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चियों व महिलाओं के यौन, शारीरिक और मानसिक शोषण के गंभीर तथ्य सामने आए थे। उन्होंने सवाल किया कि जो सरकार असहाय बेटियों के आश्रय-गृह को सुरक्षित नहीं रख पाई, उसके प्रतिनिधि आज महिला सुरक्षा पर किस नैतिक अधिकार से बोल रहे हैं। सैनी ने जुलाई 2012 में मानेसर स्थित मारुति सुजुकी संयंत्र में हुई हिंसा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि घटना में मानव संसाधन महाप्रबंधक अवनीश कुमार देव की जान गई, कई अधिकारी व कर्मचारी घायल हुए तथा आगजनी और तोड़फोड़ से हरियाणा की औद्योगिक छवि प्रभावित हुई। उन्होंने 2014 के हिसार के भगाणा गांव में चार दलित नाबालिग लड़कियों के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 'डायल-112' को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा, महिला, यातायात, साइबर, दुर्गा शक्ति, एनएचएआई और आपदा प्रबंधन सहित 10 आपातकालीन सेवाओं को इससे जोड़ा गया है। प्रदेश में 630 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में तैनात किया गया है। सरकार ने 250 अतिरिक्त वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वांछित, उद्घोषित, जमानत या पैरोल से फरार तथा अन्य सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' चलाया जा रहा है। 1 से 15 अगस्त 2026 तक चले अभियान में 4,771 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 216 हथियार, 287 कारतूस और 15 मैगजीन बरामद की गईं। 241 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई, जबकि 1,406 हिस्ट्रीशीट अपडेट की गईं।

उन्होंने बताया कि एक से 15 दिसंबर 2025 तक चले 'ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन' के दौरान 1,213 मामले दर्ज कर 2,200 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

चाकू की नोक पर ट्रक चालक से लूट

रायपुर, एजेंसी। तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर ट्रक चालक से नकदी और मोबाइल फोन लूटने वाले चार आरोपितों को पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

आरोपितों के कब्जे एवं निशानदेही से वारदात में प्रयुक्त चाकू, लूट की रकम, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस आरोपितों से क्षेत्र में हुई अन्य लूट, चोरी और आपराधिक घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ कर रही है।

पुलिस के अनुसार, ग्राम भरौली, थाना नरही, जिला बलिया निवासी सुनील राम वर्तमान में रायपुर के रांवाभाठा में रहकर नारायण मूर्ति ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चालक के रूप में काम करता है। 26 अगस्त को वह ट्रक में जांजगीर-चांपा से लोहा लोड कर ग्राम कोनारी स्थित श्री राम दूत इस्पात कंपनी पहुंचा था। कंपनी के बाहर ट्रक खड़ा करने के बाद वह केबिन में सो गया। 27 अगस्त की रात करीब 2 बजे चार आरोपित ट्रक के केबिन का कांच खोलकर अंदर घुस गए।

पंजाब के कर्मचारी महंगाई भत्ता (डीए) के बकाया और दूसरी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं

पंजाब में तीन लाख से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर

चंडीगढ़, एजेंसी।

पंजाब में सभी विभागों, बोर्डों और निगमों के तीन लाख से अधिक कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को हड़ताल पर चले गए। इसके कारण पंजाब में सरकारी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। पंजाब के कर्मचारी महंगाई भत्ता (डीए) के बकाया और दूसरी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। गुरुवार को सभी कर्मचारियों ने एक दिन का सामूहिक आकस्मिक अवकाश ले लिया। बताया गया कि लगभग चार लाख पेंशनभोगियों के साथ मिलकर ये कर्मचारी जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर सरकारी कार्यालयों में दिन भर धरना देंगे।

इस 'महा हड़ताल' का असर सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और शिक्षण संस्थानों में भी देखा गया। हालांकि, बाजार, प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट व पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें और इमरजेंसी सेवाएं इस बंद से बाहर रखी गई हैं। कर्मचारी यूनियनों के अनुसार, उनका 20,161 करोड़ रुपए का महंगाई भत्ता बकाया है। इसमें से 6,000 करोड़ रुपए 2021 से बकाया हैं, जबकि बाकी 14,161 करोड़ रुपए 2021 से पहले के हैं।

कर्मचारियों को मूल वेतन का 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मिल रहा है, जबकि उनका दावा है कि यह 58 प्रतिशत होना चाहिए। हालांकि, इस विषय को सुलझाने के लिए हड़ताल से एक दिन पहले राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में कई कर्मचारी संघों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने बैठक में कहा, भगवंत मान सरकार आपकी मांगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। आपकी अधिकतर मुख्य मांगों पर कार्रवाई पहले से ही चल रही है।

उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग और वित्त विभाग को निर्देश भी दिए और कहा, ₹कर्मचारी यूनियनों की जायज मांगों पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार करें। उनके जल्द समाधान के लिए जरूरी कार्रवाई में तेजी लाएं। वहीं, हड़ताल के बीच, मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को जालंधर में पंजाब आर्म्ड पुलिस (पीएपी) कॉम्प्लेक्स में कर्मचारी यूनियनों के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को सरकार को 15 दिनों के भीतर बकाया महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान करने का निर्देश दिया था। साथ ही, कोर्ट ने बकाया राशि का भुगतान होने तक राज्य को बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान चलाने से भी रोक दिया था।

स्मार्ट सिटी के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़

बल्लभगढ़, एजेंसी।

रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए घर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ते ही गुरुवार को बल्लभगढ़ और एनआईटी बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आगरा, अलीगढ़, सोहना और गुरुग्राम की ओर जाने वाली बसों में पैर रखने तक की जगह नहीं रही। यही हाल रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया। हालात ये रहे कि महिला कोच में भी पुरुष यात्री जबरन चढ़ गए। भीड़ अधिक होने से टैक्सी और निजी वाहन सेवा का यात्रियों ने लाभ लिया, हालांकि उन्हें बाकी दिनों के मुकाबले जेब ज्यादा ढ़ीली करनी पड़ी।

बसों में सीट नहीं मिलने पर कई यात्री खड़े होकर सफर करते दिखाई दिए। यही नहीं, बसों की छतों पर भी यात्रियों ने अपना ठिकाना बनाया। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने करीब 15 अतिरिक्त बसें विभिन्न व्यस्त मार्गों पर उतारीं। इससे यात्रियों को थोड़ी राहत मिली, हालांकि देररात तक बस अड्डों पर भीड़ बनी रही। गुरुवार दोपहर तक बल्लभगढ़ और एनआईटी बस अड्डों से आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर 50 से अधिक बसें रवाना हो चुकी थीं। इसके अलावा सोहना। गुरुग्राम, पलवल और नूंह सहित अन्य मार्गों पर भी अतिरिक्त बसें चलाई गईं। रोडवेज प्रबंधन ने यात्रियों की संख्या को देखते हुए कॉलेज के विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाली कुछ बसों को भी व्यस्त मार्गों पर लगा दिया। इस दौरान अपनी जान जोखिम में डाल कर बसों की छत पर भी यात्रा की। फरीदाबाद से 30 से अधिक मार्गों पर रोजाना करीब 125 बसों का परिचालन होता है।

इनमें कई बसें अपने निर्धारित मार्ग के बस अड्डों पर रात में ठहरती हैं। रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की बढ़ी संख्या को देखते हुए ऐसी बसों का रात्रि ठहराव भी निरस्त कर उन्हें वापस बुलाया गया है। इससे दिन के समय अधिक बसें यात्रियों के लिए उपलब्ध हो सकेंगी।

सोनल दिनुषा ने जड़ा लगातारा दूसरा शतक, श्रीलंका ने 'ड्रॉ' करवाया मैच

भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि सारांश जैन को 2 सफलताएं हाथ लगीं।

कोलंबो,एजेंसी। भारत-श्रीलंका के बीच सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच 'ड्रॉ' पर समाप्त हुआ। इसी के साथ टीम इंडिया ने 2 मुकाबलों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। गुरुवार को मुकाबले के पांचवें दिन मेजबान देश ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर 429 रन बना लिए थे, जिसके बाद दोनों देशों ने ड्रॉ पर सहमति जताई। भारतीय टीम चाहती थी कि वह मुकाबले के पांचवें दिन श्रीलंकाई टीम के अंतिम 4 विकेट जल्द लेकर आसान टारगेट को हासिल करते हुए जीत दर्ज करे, लेकिन सोनल दिनुषा ने मुकाबले की लगातार दूसरी पारी में शतक लगाकर मेहमान टीम के इरादों पर पानी फेर दिया।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की। इस पारी में देवदत्त पड्डिकल और शुभमन गिल के बीच 120 रन की साझेदारी हुई, जबकि ऋषभ पंत ने ध्रुव जुरेल के साथ 112 रन जोड़े। पड्डिकल ने 12 चौकों के साथ 117 रन की पारी खेली, जबकि जुरेल ने नाबाद 115 रन बनाए। पंत 63 रन और कप्तान गिल 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विपक्षी खेमे से असिथा फर्नांडो ने 4 विकेट चटकाए, जबकि प्रभात जयसूर्या और केशरा नुवानथा ने 2-2 विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई। मेजबान टीम ने 35 के स्कोर तक 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद पसिंदु सूरियाबंदारा (80) ने कामिंदु मेंडिस (32) के साथ चौथे विकेट के लिए 87 रन जोड़कर टीम को संभाला। श्रीलंका ने 173 के स्कोर तक 7 विकेट खो दिए थे। इसके बाद सोनल दिनुषा (103) ने मोर्चा संभाला। उन्होंने केशरा नुवानुथा के साथ 57 रन, जबकि लाहिरू कुमारा (12) के साथ 58 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 290 के स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन फॉलोऑन नहीं बचा सके।

भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि सारांश जैन को 2 सफलताएं हाथ लगीं। भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 63 के स्कोर तक 2 विकेट खो दिए थे। इसके बाद पसिंदु सूरियाबंदारा ने कामिंदु मेंडिस के साथ तीसरे विकेट के लिए 115 रन जोड़कर टीम को 178 के स्कोर तक पहुंचाया।

सूरियाबंदारा 92 रन बनाकर पवेलियन लौटे। चौथे दिन की समाप्ति तक मेजबान टीम ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 229 रन बना लिए थे। यहां से उसके पास सिर्फ 16 रन की बढ़त थी, लेकिन अंतिम दिन भारतीय टीम श्रीलंका के आखिरी 4 विकेट हासिल नहीं कर सकी। सोनल दिनुषा ने केशरा नुवानुथा के साथ सातवें विकेट के लिए 112 रन जोड़। केशरा 4 चौकों के साथ 46 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सोनल ने मोर्चा संभाले रखा। सोनल अंत तक क्रीज पर टिके रहे। उन्होंने 264 गेंदों में 2 छक्कों और 8 चौकों के साथ 133 रन की नाबाद पारी खेली।

आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ को अंडर-19 टीम में बुलावा

मुम्बई,एजेंसी। दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग को पहली बार भारतीय अंडर-19 टीम में चुना गया है। उन्हें सितंबर में राजकोट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज आर्यवीर ने हाल ही में चल रही दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए खेला, जहां उनके आक्रामक खेल की तुलना उनके पिता से की गई। इससे पहले 2024 में कूच बिहार ट्रॉफी के दौरान मेघालय के खिलाफ 297 रन बनाकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी थीं।

वनडे टीम में विकेटकीपर अन्वय द्रविड़ भी शामिल हैं, जिन्होंने जुलाई में श्रीलंका के दौरे पर अंडर-19 टीम के लिए शानदार 87 रन बनाकर अपनी जगह बनाए रखी है। हालांकि, आर्यवीर और अन्वय दोनों में से किसी को भी दो मल्टी-डे मैचों की टीम में नहीं चुना गया है। सलामी बल्लेबाज लक्ष्य रायचंदानी वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि श्रीलंका दौरे पर भारत की कप्तानी करने वाले यशवर्धन चौहान उनके उपकप्तान होंगे। हालांकि, मल्टी-डे मैचों के लिए दोनों खिलाड़ी अपनी भूमिकाएं बदल लेंगे। भारत राजकोट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलेगा, जो 18, 21 और 23 सितंबर को होंगे। राजकोट 27-30 सितंबर तक पहले मल्टी-डे मैच की भी मेजबानी करेगा, जबकि दूसरा मल्टी-डे मैच 5-8 अक्टूबर तक अहमदाबाद (बी ग्राउंड) में खेला जाएगा। इंडिया अंडर-19 वन-डे टीमः- लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशवर्धन चौहान (उप-कप्तान), रजत बघेल, आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़, वी यशवीर, रोहित यादव, शविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट और काव्या पटेल।

सेरेना और वीनस को यूएस ओपन युगल के लिए मिला वाइल्ड कार्ड

वॉशिंगटन,एजेंसी। अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना और वीनस विलियम्स बहने यूएस ओपन टूर्नामेंट के महिला युगल मुकाबले में एक बार फिर से खेलती नजर आयेगी। इन दोनों खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश मिला है। यूएस ओपन की ओर से बुधवार को यह घोषणा की गई। दोनों बहनें, जिन्होंने साथ मिलकर 14 प्रमुख युगल खिताब जीते हैं, लगभग चार साल के अंतराल के बाद पिछले सप्ताह सिनसिनाटी ओपन में एक जोड़ी के रूप में वापसी की।

यह यूएस ओपन में युगल मुकाबले में उनकी नौवीं संयुक्त उपस्थिति होगी और 2022 के बाद पहली बार। उन्होंने 1999 और 2009 में न्यूयॉर्क में खिताब जीता था। 44 वर्षीय सेरेना विलियम्स ने 2022 यूएस ओपन के बाद टेनिस से कुछ समय के लिए दूरी बनाने के बाद जून में प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी की। मूल रूप से, सेरेना और 46 वर्षीय वीनस को जुलाई में विंबलडन में एक साथ खेलना था, लेकिन ऑल इंग्लैंड क्लब में पहले दौर के एकल मैच में घुटने में चोट लगने के बाद उन्होंने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया।

सेरेना यूएस ओपन में केवल युगल ही खेलेंगी। मंगलवार को उन्होंने कार्लोस अल्काराज के साथ मिश्रित युगल में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन बेलिंडा बेनसिक और फ्लेवियो कोबोली ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया ।

हमें अभी से ही ओलंपिक 2036 खेलों तैयारी शुरु करनी होगी: मोदी

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ओलंपिक खेलों में भागीदारी बढ़ाने और ओलंपिक 2036 के लिए तैयारी अभी से शुरू करने का आह्वान करते हुए कहा कि देश का खेल विजन केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 'विकसित भारत' के निर्माण में खेल और युवाओं की ताकत का उपयोग करने के एक बड़े मिशन का हिस्सा है।

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'खेलो इंडिया डायलॉग' को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने खेल, युवा नेतृत्व, फिटनेस, नागरिक जिम्मेदारी और राष्ट्र-निर्माण पर देशव्यापी चर्चा के तहत देशभर के युवाओं से बातचीत की। 'मेरा युवा भारत' द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जुड़ने, अपनी उम्मीदें साझा करने और देश के युवा और खेल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विचार देने का मंच प्रदान करना है।

इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भागीदारी हो रही है, जिसमें प्रत्येक जिले के दो कॉलेजों के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान लाल किले की प्राचीर से भारत के व्यापक खेल विजन की रूपरेखा बताई थी। उन्होंने कहा, जब मैं खेल की बात करता हूं, तो यह केवल पदक जीतने के बारे में नहीं है। यह एक विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और युवा शक्ति को एक साथ लाने का अभियान है। भारत के लिए अधिक अंतरराष्ट्रीय खेलों में प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने ऐतिहासिक रूप से ओलंपिक में शामिल लगभग आधी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया है। ऐसा दशकों से चला आ रहा है। उन्होंने कहा, दूसरे देश उन खेलों में पदक जीतते हैं जिनमें हम भाग भी नहीं लेते।

भारत दौरे की वजह से न्यूजीलैंड में टिकटों की रिकॉर्ड मांग

क्राइस्टचर्च,एजेंसी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के इंटरनेशनल समर क्रिकेट ने रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की है। क्रिकेट नेशन मेंबर्स की प्री-सेल के पहले 48 घंटों के अंदर 26,000 टिकट बिक गए। टिकटों की जबरदस्त मांग भारत दौरे की वजह से है। भारतीय टीम अक्टूबर में मल्टी-फॉर्मेट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। इस दौरे पर 12 मैच खेले जाने हैं। ऑकलैंड के ईडन पार्क में व्हाइट-बॉल मैच शुरुआती बिक्री में सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरा हैं। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में भी टिकटों की जबरदस्त मांग देखी गई है।

9,000 की क्षमता वाले इस वेन्यू पर 22 और 24 अक्टूबर को होने वाले शुरुआती दो टी20 के साथ-साथ 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक होने वाले टूर के दूसरे और आखिरी टेस्ट के लिए भी टिकट बिक जाने की उम्मीद है। वेलिंगटन में भी टिकटों की बिक्री जोरों पर है। यहां तीसरा टी20 और दूसरा वनडे खेला जाना है। पहला टेस्ट, जो 19 नवंबर से शुरू होगा, बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ मार्केटिंग और कमर्शियल ऑफिसर ग्लेन क्रिचली ने कहा कि शुरुआती रिस्पॉन्स भारत के दौरे को लेकर उत्साह दिखाता है।

शुरू से ही फैन्स के लिए हमारा संदेश यही रहा है कि वे कुछ भी मिस न करने के लिए तैयार रहें।

बिजनेस

सोना बढ़त के साथ खुला, चांदी का दाम 2.40 लाख के पार

मुंबई,एजेंसी। सोने और चांदी की शुरुआत गुरुवार को तेजी के साथ हुई। हालांकि, दोनों कीमती धातुओं का दाम एक सीमित दायरे में बना हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अक्टूबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,59,663 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 836 रुपए की तेजी के साथ 1,60,499 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला।

चैटजीपीटी भारत में फ्री और गो टियर यूजर्स के लिए शुरू करेगा विज्ञापन

नई दिल्ली,एजेंसी। अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनी ओपनएआई ने भारत में 'चैटजीपीटी ऐड' का विस्तार करने की घोषणा की है। भारत कंपनी के सबसे बड़े बाजारों में से एक है।

पीयूष गोयल के जापान दौरे से भारत-जापान आर्थिक सहयोग को मिली नई गति

नई दिल्ली,एजेंसी। सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के जापान दौरे ने भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को नई मजबूती प्रदान की है। इस यात्रा ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के प्रयासों को नया प्रोत्साहन दिया है। साथ ही भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और निवेश केंद्र बनाने की दिशा में जापानी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने की मजबूत नींव भी रखी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि टोक्यो, नागोया और ओसाका में आयोजित उच्चस्तरीय बैठकों और कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुई इस आधिकारिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य जापानी निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना और उभरते तथा रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का विस्तार करना था।

दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने जापान सरकार के वरिष्ठ नेताओं, प्रमुख वित्तीय संस्थानों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा की। उन्होंने भारत में निवेश की संभावनाएं तलाश रही या पहले से कारोबार कर रही 30 से अधिक प्रमुख जापानी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। इन चर्चाओं में निवेश विस्तार, मजबूत और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, तकनीकी सहयोग और दोनों देशों के उद्योगों के बीच नए व्यावसायिक अवसरों पर विशेष जोर दिया गया।

इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत के लिए दीर्घकालिक जापानी संस्थागत पूंजी को आकर्षित करना भी था। इसी क्रम में गोयल ने एमयूएफजी, मिजुहो, नोमुरा, निप्पॉन लाइफ, डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान और मॉर्गन स्टेनली एमयूएफजी सिक्योरिटीज सहित कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों के नेताओं से मुलाकात की। इन बैठकों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और वित्तीय क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित विशेष गोलमेज बैठकों की भी अध्यक्षता की।

इन बैठकों में भारतीय और जापानी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा का केंद्र ठोस निवेश परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायिक सहयोग के अवसर तलाशना था। खासतौर पर भारत के टियर-2 और टियर-3 आपूर्तिकर्ता नेटवर्क तथा एमएसएमई क्षेत्र को जापानी उद्योगों के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया।

पीयूष गोयल ने जापानी निवेशकों के सामने भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की संभावनाओं को भी प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2032 तक भारत में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

उन्होंने सरकार की छह स्तंभों वाली रणनीति का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर मशीनरी एवं सामग्री, चिप निर्माण, एटीएमपी/ओसैट, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा विकास जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। दौरे के दौरान गोयल ने जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्री अकाजावा रयोसेई से भी मुलाकात की। इसके अलावा, उन्होंने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो)।

लगातार दूसरे दिन गिरा बाजार, सेंसेक्स 539 अंक फिसला

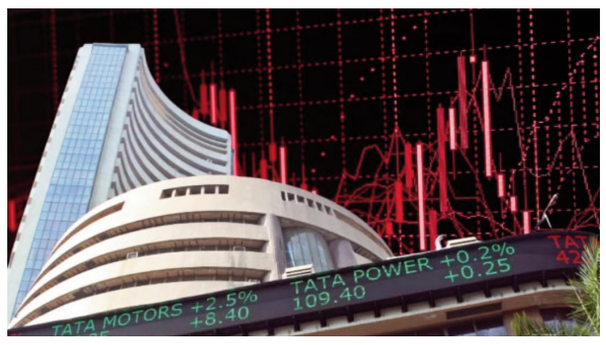

मुंबई,एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी तनावों के बीच वैश्विक बाजारों के मिले-जुले संकेतों के चलते हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। इस दौरान मेटल, पीएसयू बैंकों और सीमेंट के शेयरों में गिरावट के चलते घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्क निफ्टी और सेंसेक्स में 0.70 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 539.35 अंक यानी 0.70 प्रतिशत गिरकर 76,933.59 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी50 116.90 अंक यानी 0.48 प्रतिशत गिरकर 24,090.85 पर आ गया।

व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.10 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, सेक्टरवार देखें तो निफ्टी सीमेंट में सबसे ज्यादा 1.33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.94 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया में 89 प्रतिशत, निफ्टी मेटल में 0.86 प्रतिशत और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.51 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। वहीं, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी प्राइवेट बैंक ने बेहतर प्रदर्शन किया।

निफ्टी50 इंडेक्स में अदाणी इंटरप्राइजेस, कोटक महिंद्रा बैंक, अदाणी पोर्ट्स, सिप्ला और बीईएल के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई और ये दिन के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे, जबकि हिंडाल्को, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल और रिलायंस के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई और ये शीर्ष नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल रहे।

भारत का टैबलेट बाजार 2026 की पहली छमाही में 15 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत के टैबलेट बाजार में 2026 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि प्रीमियम डिवाइसों की बढ़ती मांग और कंज्यूमर, शिक्षा और एंटरप्राइज क्षेत्रों में लगातार मांग के कारण हुई। साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, 20,000 रुपए से अधिक कीमत वाले प्रीमियम टैबलेट्स की बिक्री सालाना आधार पर 74 प्रतिशत बढ़ी और इनकी बाजार हिस्सेदारी 89 प्रतिशत रही। इससे बेहतर परफॉर्मेंस, बड़े डिस्प्ले और अधिक उत्पादकता वाले डिवाइसों की बढ़ती मांग का संकेत मिलता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि 10 इंच से बड़े स्क्रीन वाले टैबलेट्स की कुल शिपमेंट में करीब 91 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। वहीं, वाई-फाई टैबलेट्स का शिपमेंट 30 प्रतिशत बढ़ा, 5जी टैबलेट्स में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 4जी टैबलेट्स की शिपमेंट में 19 प्रतिशत की गिरावट आई। मांग का रुझान अधिक बेहतर परफॉर्मेंस वाले कॉन्फिगरेशन की ओर भी रहा। 6जीबी रैम वाले टैबलेट्स की बिक्री 73 प्रतिशत बढ़ी, जबकि 12जीबी रैम वाले वेरिएंट्स में 422 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल ने अपनी बढ़त और मजबूत की। अकेले एप्पल आईपैड 11 सीरीज की भारत में प्रीमियम टैबलेट शिपमेंट में करीब 23 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।

साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) की वरिष्ठ विश्लेषक मेनका कुमारी ने कहा, भारतीय टैबलेट बाजार तेजी से परिपक्व हो रहा है और इसमें ज्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन वाले डिवाइसों की ओर स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। कंपोनेंट की बढ़ती लागत के साथ-साथ बड़े स्क्रीन, ज्यादा रैम और मजबूत वाई-फाई कनेक्टिविटी को लेकर उपभोक्ताओं की प्राथमिकता औसत बिक्री कीमतों को ऊपर ले जा रही है।

कुमारी ने कहा, भले ही कुल बिक्री में वृद्धि की रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन, शिक्षा और एंटरप्राइज प्रोडक्टिविटी के लिए टैबलेट अभी भी महत्वपूर्ण डिवाइस बने हुए हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि कैलेंडर वर्ष 2026 में भारत का टैबलेट बाजार 10-12 प्रतिशत तक घट सकता है।

भर्ती प्रक्रिया में एआई का तेजी से बढ़ रहा प्रभाव तकनीक: रिपोर्ट

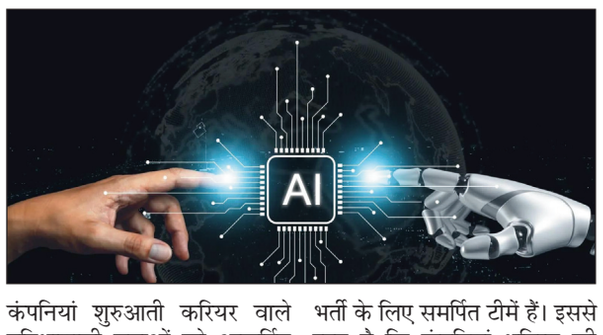

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत में भर्ती प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और एजेंटिक एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 86 प्रतिशत भारतीय संगठनों का मानना है कि एआई उनकी भर्ती प्रक्रिया को बदल रही है। रिज्यूमे की जांच, उम्मीदवारों का मूल्यांकन और भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के साथ संवाद जैसे क्षेत्र एआई के प्रमुख उपयोग के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

डेलॉइट इंडिया की 'कैंपस वर्कफोर्स ट्रेंड्स 2026' रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कैंपस भर्ती अब पहले की तुलना में अधिक रणनीतिक, कौशल-आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित हो गई है। कंपनियां शुरुआती करियर वाले प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करने के लिए अधिक निवेश कर रही हैं और इंटर्नशिप से स्थायी नौकरी तक पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को मजबूत बना रही हैं। अध्ययन में पाया गया कि भर्ती बजट में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि 80 प्रतिशत संगठनों के पास अब कैंपस भर्ती के लिए समर्पित टीमें हैं। इससे स्पष्ट है कि कंपनियां भविष्य की कार्यबल तैयार करने के लिए संस्थागत स्तर पर निवेश बढ़ा रही हैं।

एआई के उपयोग में रिज्यूमे स्क्रीनिंग सबसे प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है, जहां 72 प्रतिशत कंपनियां इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा, 35 प्रतिशत संगठनों का कहना है कि एआई के बढ़ते उपयोग के चलते नई शुरुआती स्तर की नौकरियां (एंट्री-लेवल पद) और नए कौशलों की मांग पैदा हो रही है, जो पिछले वित्त वर्ष 2025 में 21 प्रतिशत थी। रिपोर्ट के अनुसार, एआई और डेटा से जुड़े कौशल रखने वाले उम्मीदवारों को भर्ती के दौरान 20 से 25 प्रतिशत तक अधिक वेतन मिलने की संभावना है।

वहीं विश्लेषणात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमता जैसे कौशल रखने वाले उम्मीदवारों को भी 10 से 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त वेतन प्रीमियम मिल रहा है। अध्ययन में यह भी सामने आया कि इंटर्नशिप अब स्थायी नौकरी का अधिक प्रभावी माध्यम बन रही है। विभिन्न शैक्षणिक श्रेणियों में प्री-प्लेसमेंट ऑफर में रूपांतरण की दर बेहतर हुई है। कंपनियों के अनुसार, किसी इंटर्न को स्थायी नौकरी मिलने की संभावना का सबसे बड़ा आधार उसकी व्यवहारिक दक्षता (75 प्रतिशत) और सीखने की क्षमता (72 प्रतिशत) है। बेहतर प्रतिभा चयन और कौशल मिलान के कारण शुरुआती स्तर पर नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में भी कमी आई है। शीर्ष संस्थानों और टियर-1 कॉलेजों से भर्ती किए गए कर्मचारियों में शुरुआती त्याग दर 18 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह गई है।

रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 2022 से 2026 के बीच वेतन वृद्धि की औसत वार्षिक दर 2 से 4 प्रतिशत रही है।

करीना कपूर ने 'दायरा' को बताया ड्रीम प्रोजेक्ट

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री करीना कपूर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'दायरा' की रिलीज की तैयारी में हैं। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोजेक्ट पर काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताया।

अभिनेत्री करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर कर बताया कि इस फिल्म ने उन्हें मुंबई के उन हिस्सों और ऐसी जगहों पर पहुंचाया, जहां वह पहले कभी नहीं गई थीं। करीना ने कहा कि भले ही वह पूरी जिंदगी इसी शहर में रही हैं और पूरे भारत में घूमी हैं, लेकिन 'दायरा' ने उन्हें मुंबई का एक अनदेखा पहलू दिखाया।

अभिनेत्री ने लिखा, 'मुंबई में मेरा जन्म हुआ। सारी जिंदगी इस शहर में रहते हुए देशभर में काफी सफर करने के बाद, मुझे लगता था कि मैं इस शहर और देश को अच्छे से जानती हूं, लेकिन फिल्म दायरा की शूटिंग के दौरान मैं ऐसी-ऐसी जगहों पर गईं, जो मैंने पहले कभी ना देखी थी और ना जानती थी।'

अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म दायरा ने उनकी सामाजिक समझ को भी कई नई हदों तक पहुंचाया। उन्होंने लिखा, ₹दायरा का सफर मेरी रचनात्मकता को उन जगहों तक ले गया, जो मेरे लिए अब तक अनजान थे। दायरा ने मेरी सामाजिक समझ को भी कई नई हदों तक पहुंचाया। मैंने सीखा है कि हमारी जिंदगी और समाज सिर्फ दोहरा नहीं है, सब कुछ सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। इनके बीच एक पूरा स्पेक्ट्रम है, ग्रे का एक पूरा संसार है, जिसमें हम जीते हैं। दायरा उस ग्रे को सिर्फ समझने की कोशिश नहीं करती बल्कि, ये उसके अंदर उतरती है, उसे कुरेदती है। यही दायरा का सार है। क्योंकि दायरा की दुनिया पूरी तरह ग्रे है, लेकिन इसके साथ-साथ, हमेशा दोहरी भी है।'

उन्होंने आगे लिखा, 'यह फिल्म हमेशा से ही दोहरी कहानी वाली रही है। अपने मूल में 'दायरा' सिर्फ दोहराव के बारे में है और यह दोहरापन फिल्म के दो मुख्य किरदारों के जरिए दिखाया गया है। कास्टिंग के लिहाज से, यह मेरे लिए सपने के सच होने जैसा था। हिंदी और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दो बेहतरीन कलाकारों को एक-दूसरे के सामने लाना। क्योंकि 'दायरा' एक ऐसी कहानी है जो एक नहीं, बल्कि देश भर में हुई कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। दायरा की कहानी भारत के किसी एक शहर या राज्य में नहीं घटती, बल्कि यह हमारे देश में लगभग हर जगह घटती है। दायरा की इस दुनिया को बेहतरीन कलाकारों और शानदार टीम ने जीवंत किया है।'

उन्होंने बताया कि इस कहानी में दोनों कलाकार कानून के सफर में हैं, लेकिन फिर, दोंनो खुद को कानून की नाजुक लकीरों के आर-पार पाते हैं। फिल्म में मैंने अजूनी का किरदार निभाया है, जो अपने उसूलों को लेकर अटूट है और पृथ्वीराज के रमन के तेवर भी उनके उसूल जितने मजबूत हैं। जिंदगी की तरह, दायरा में भी, दोनों के फैसले न काले हैं, न सफेद। दोनों ग्रे के एक ऐसे इंद्रधनुष में घुले हैं, जहां कुछ भी साफ-साफ, सही या गलत नहीं है। कभी कानून उन्हें रास्ता दिखाता है, तो कभी वही कानून उनके रास्ते रोक देता है। कानून की लकीरों के दरम्यान का सफर, है दायरा।'

करीना ने बताया कि इस फिल्म में वे बिल्कुल नए अंदाज में नजर आने वाली हैं। उन्होंने लिखा, 'दायरा में मेरा बिल्कुल ही नया और अनदेखा पहलू नजर आयेगा उसे पढ़ पाना आसान नहीं है। वो मुश्किल हालात और लोगों पर मुस्कुराते हुए काबू पा लेती है। पृथ्वीराज सुकुमारन का निभाया हुआ रमन, जैसे अजूनी का दूसरा पहलू है। अपने गुस्से को अंदर ही अंदर कैद कर रखा है और वो कभी मुस्कुराता नहीं।'

पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी भाई-बहन हैं ये सेलेब्स

मुंबई। भाई-बहन का रिश्ता सिर्फ जन्म से ही नहीं बल्कि यह भागवानओं और निस्वार्थ प्यार का अटूट बंधन है। माता-पिता के अलावा भाई-बहन एक दूसरे के लिए सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम होते है। मनोरंजन जगत में ऐसे कई सेलेब्स हैं, जो पर्दे के साथ-साथ असल जिंदगी में भी भाई-बहन हैं।

फरहान अख्तर और जोया अख्तरः यह भाई-बहन की जोड़ी बॉलीवुड में निर्देशक, निर्माता और कलाकार के रूप में जानी जाती है। दोनों ने साथ में मिलकर कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनमें 'दिल चाहता है' और 'ज़िन्दगी ना मिलेगी दोबारा' जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। दरअसल, फरहान अख्तर और जोया अख्तर प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर और पटकथा लेखक हनी ईरानी की संतान हैं।

हुमा कुरैशी और साकिब सलीमः ये दोनों ही बॉलीवुड के मशहूर और प्रतिभाशाली अभिनेता और अभिनेत्री हैं। उनके पिता सलीम कुरैशी दिल्ली में 'सलीम' नामक रेस्टोरेंट की एक मशहूर श्रृंखला चलाते हैं। दोनों भाई-बहन ने मिलकर 'सलीम सिबलिंग्स' नाम से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया है, जिसके तहत वे फिल्मों का निर्माण कर

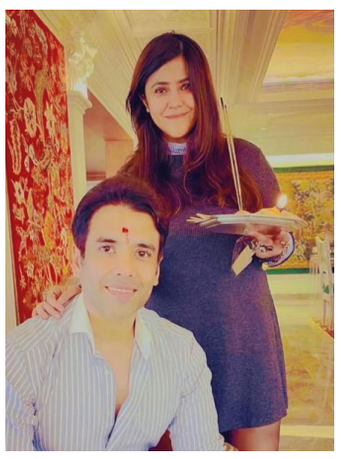

रहे हैं।

श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूरः अभिनेता शक्ति कपूर के ये दोनों बच्चे बॉलीवुड के मशहूर और लोकप्रिय कलाकारों में शामिल हैं। श्रद्धा एक शीर्ष अभिनेत्री हैं जबकि सिद्धांत ने भी कई फिल्मों में अभिनय और सहायक निर्देशन किया है। सोशल मीडिया पर दोनों की हल्की-फुल्की नोकझोंक और मस्ती-मजाक देखने को मिलता है। दोनों फिल्म 'हसीना पारकर' में एक साथ नजर आए थे। 2017 में रिलीज हुई फिल्म 'हसीना पारकर' में श्रद्धा कपूर ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (सिद्धांत कपूर) की बहन हसीना पारकर का मुख्य किरदार निभाया था।

वरुण तेज और निहारिका कोनिडेलाः दोनों प्रसिद्ध अभिनेता-निर्माता नागेंद्र बाबू (नागा बाबू) और पद्मजा कोनिडेला के बच्चे हैं। वरुण तेज एक जाने-माने तेलुगु अभिनेता हैं। उनकी बहन निहारिका कोनिडेला अभिनेत्री और निर्माता हैं। वह अपनी आने वाली फिल्म 'भारी' का निर्माण कर रही हैं, जिसमें वरुण तेज मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

देवयानी और नकुल : देवयानी और नकुल दक्षिण भारतीय सिनेमा (मुख्य रूप से तमिल फिल्म उद्योग) के जाने-माने एक्टर हैं। दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब हैं और अक्सर एक-दूसरे के कार्यक्रमों में नजर आते हैं। एकता कपूर और तुषार कपूरः तुषार कपूर एक अभिनेता हैं जबकि एकता कपूर पर्दे के पीछे रहकर बालाजी टेलीफिल्म्स के जरिए भारतीय टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट की दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक हैं। एकता कपूर और तुषार कपूर प्रसिद्ध अभिनेता जितेंद्र के बच्चे हैं।

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की 'द वन' का टीज़र दिखाता है रहस्य और रोमांच से भरी फोकलोर की अनदेखी दुनिया!

'द वन' का टीज़र सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया को लेकर जाता है रहस्यों और रोमांच से भरी फोकलोर की एक अनोखी दुनिया मेंबड़े पर्दे पर एक अनदेखी दुनिया की झलक लेकर आया है 'द वन' का टीज़र। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फ्रेश जोड़ी पहली बार एक साथ नजर आ रही है और दोनों एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में दाखिल होते दिखाई देते हैं, जहां हर कदम के साथ एक नया रहस्य सामने आता है।

बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत 'द वन' का टीज़र हिंदी सिनेमा में कम देखी गई फोकलोर की एक अनोखी दुनिया से रूबरू कराता है। प्राचीन मान्यताओं, रहस्यों और अलौकिक शक्तियों से जुड़ी इस दुनिया की पहली झलक ही दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा देती है। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य उस जंगल से जुड़ा है, जहां सूर्यास्त के बाद जाना सख्त मना है—"सूर्यास्त के बाद, वन में प्रवेश करना

वर्जित है।"

टीज़र में फिल्म का भव्य विजुअल ट्रीटमेंट भी खास ध्यान खींचता है। 'द वन' फोकलोर और फैंटेसी को बड़े पैमाने पर पर्दे पर पेश करती नजर आ रही है। शानदार विजुअल्स, रहस्यमयी माहौल और दमदार साउंडस्केप मिलकर दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग है। फिल्म का संगीत भी इस अनुभव को खास बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसमें रहस्य और रोमांच के साथ भारतीय मिट्टी और भक्ति की झलक भी महसूस होती है, जो फिल्म की दुनिया को एक खास पहचान देती है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फ्रेश जोड़ी टीज़र का एक और बड़ा आकर्षण है। दोनों की स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रहस्यमयी दुनिया के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। टीज़र उनकी कहानी को लेकर कई सवाल छोड़ जाता है—आखिर उनके किरदारों के बीच क्या रिश्ता है और इस रहस्यमयी वन में उनका सामना किससे होने वाला है?

विदेश

नेपाल त्रासदी: अमेरिका ने बढ़ाया मदद का हाथ

वॉशिंगटन। अमेरिका नेपाल के रसुवा जिले में आई विनाशकारी अचानक बाढ़ के बाद एक डिजास्टर रिस्पॉन्स एडवाइजर भेज रहा है और पांच लाख डॉलर की आपातकालीन सहायता भी प्रदान कर रहा है। इस आपदा में कई लोगों की जान गई है और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस सहायता की घोषणा की।

अल्जीरिया के जंगलों में लगी भीषण आग: 12 की मौत

अल्जीयर्स। अल्जीरिया के पूर्वोत्तर हिस्से में भीषण जंगल की आग ने तबाही मचा दी है। प्रशासन के अनुसार, आग की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेब्बौने के निर्देश पर गृह मंत्री सईद सयूद ने गुरुवार को बेजाया और फिर जिजेल प्रांत का दौरा किया।

'नालंदा: हाउ इट चेंज्ड द वर्ल्ड' पर यूनेस्को हाउस में मंथन, लेखक अभय के. ने बताया कैसे नालंदा से बदली दुनिया

नई दिल्ली। यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की ओर से भारत में लेखक और राजनयिक अभय के. की पुस्तक 'नालंदाः हाउ इट चेंज्ड द वर्ल्ड' पर एक विशेष कार्यक्रम 'कॉन्वर्सेशंस ऑन नालंदा' यूनेस्को हाउस में आयोजित किया गया। इस मौके पर दक्षिण एशिया के लिए यूनेस्को प्रमुख टिम कर्टिस ने भारत के अजरबैजान में राजदूत अभय के., नालंदा विश्वविद्यालय के भाषा एवं साहित्य विद्यालय के प्रोफेसर डी. वेंकट राव और हमारे रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर स्टीफन प्रीस्नर का हार्दिक स्वागत कयिा। इस चर्चा में राजनयिकों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और छात्रों ने भाग लिया और प्राचीन शिक्षा केंद्र नालंदा तथा उसकी वैश्विक विरासत पर विचार साझा किए।

चर्चा के दौरान अभय के. ने बताया कि नालंदा की शैक्षणिक परंपरा बहुत व्यापक थी। यहां खगोल

विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन और कविता जैसे अनेक विषयों का अध्ययन और शोध किया जाता था। उन्होंने बताया कि नालंदा की शिक्षा प्रणाली बहुविषयक (इंटरडिसिप्लिनरी) थी, यहां विविध पृष्ठभूमि के विद्वान अध्यापक थे और योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जाती थीं। उनके अनुसार, ये विशेषताएं आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी एक प्रेरणादायक मॉडल बन सकती हैं।

चर्चा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय के आधुनिक पुनर्जीवन और भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उसकी नई भूमिका पर भी ध्यान दिया गया। राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में किया था। इसे प्राचीन नालंदा की विरासत को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।दक्षिण एशिया के लिए यूनेस्को प्रमुख टिम कर्टिस ने कहा, 'मैं संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन यूनेस्को के साथ मिलकर किया।'

दक्षिण एशिया के लिए यूनेस्को प्रमुख टिम कर्टिस ने कहा कि यूनेस्को कई क्षेत्रों में काम करता है, जिनमें विश्व धरोहर (वर्ल्ड हेरिटेज) भी शामिल है। नालंदा एक विश्व धरोहर स्थल है। भारत की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है और देश में 45 विश्व धरोहर स्थल हैं। यह विरासत संरक्षण के प्रति लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि जब नालंदा को सूची में शामिल किया गया तो उसे उसके 'असाधारण सार्वभौमिक महत्व' के आधार पर मान्यता दी गई। यह मान्यता दो प्रमुख मानदंडों पर आधारित थी।पहला है 'मानदंड 4': नालंदा ने संस्थानों की स्थापना, स्थल नियोजन, वास्तुकला और कलात्मक परंपराओं के ऐसे सिद्धांत स्थापित किए, जिनमें विशेष रूप से चौकोर विहार संरचना, पंचबिंदु शैली वाले चैत्य, स्टुको कला और धातु कला शामिल हैं। इन परंपराओं को बाद में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई समान संस्थानों ने अपनाया। इसका मतलब है कि नालंदा केवल अपने समय का एक अनोखा केंद्र नहीं था, बल्कि इसने पूरे क्षेत्र की वास्तुकला और शैक्षणिक परंपराओं को प्रभावित किया।दूसरा है 'मानदंड 6': नालंदा महाविहार उस उच्चतम चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जहां एक मठवासी संस्था विकसित होकर विश्वविद्यालय बनी। इसने बौद्ध धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र और ज्ञान-विमर्श की परंपराओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही, बहस और गुरु-शिष्य परंपरा जैसी विशिष्ट शिक्षण पद्धतियों को भी बढ़ावा दिया। इसकी निरंतरता आज भी दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई मठों में देखी जा सकती है।असाधारण सार्वभौमिक महत्व के इस बयान में यह भी कहा गया है कि नालंदा आज भी क्षेत्र के आधुनिक विश्वविद्यालयों को प्रेरित करता है, जिनमें वर्तमान नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल है।टिम कर्टिस ने आगे कहा कि विश्व धरोहर सूची में शामिल होना सिर्फ एक सम्मानजनक पहचान नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है।

उत्तर कोरिया का पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण हमारा लक्ष्य: अमेरिका

सोल। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के अपने लक्ष्य को दोहराया है। दावा किया है कि उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के बीच संभावित शिखर वार्ता को लेकर अटकलें तेज हैं।

योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, "अमेरिका उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।" विभाग ने ईमेल से इसका जवाब दिया। यह प्रतिक्रिया योनहाप न्यूज एजेंसी के उस सवाल के जवाब में दी, जिसमें पूछा गया था।

जेलेंस्की का दावा: रूस बढ़ा रहा अपनी युद्ध क्षमता

नई दिल्ली। यूक्रेन में रूसी हमले लगातार जारी हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि बुधवार को रूस ने एक बार फिर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन में तबाही मचाई। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस जानबूझकर नागरकि ढांचे को नशिाना बना रहा है। रूस ने कल रात भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और इमारतों पर हमले कएि।

जेलेंस्की ने दावा कयिा कि रूस युद्ध को आगे बढ़ाने के लएि अपनी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। रूस अपनी क्षमता वस्तिार और मिसाइलों के भंडार बढ़ाने के लएि काफी नविश कर रहा है।जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "रूस के हमले के बाद पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए कल रात से ही लगातार काम किया जा रहा है। यह एक संयुक्त हमला था, जिसमें ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों दोनों का इस्तेमाल किया गया।

नेपाल की सांसद बोलीं ' मुश्किल वक्त में हमारा साथ देने के लिए पीएम मोदी का आभार'

काठमांडू। नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर पीएम बालेंद्र शाह को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदूषी राणा ने ये 'भरोसा' देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है।

राणा ने आईएएनएस से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा, 'मैं वास्तव में पीएम मोदी की बहुत आभारी हूं क्योंकि जैसे ही यह घटना हुई, उन्होंने दिल छू लेने वाला बयान दिया । पीड़ित परिवारों और देश के प्रति संवेदना संदेश भेजा, वो प्रशंसनीय है। हमें भारत से पहले ही बहुत सारी राहत सामग्री मिल चुकी है। हर बार जब कोई आपदा आती है, तो हमें भारत से मदद मिलती है।'

विदूषी राणा ने स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि पूरा देश इस समय बेहद दुखद दौर से गुजर रहा है और सरकार बचाव एवं राहत

अभियानों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा, 'जो कुछ हुआ है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पूरी रात लोगों और उन परिवारों के बारे में सोचते हुए बिताई, जो अपने बच्चों और प्रियजनों के लापता होने से परेशान हैं। हम बस अच्छी खबर आने और यह जानने की उम्मीद कर रहे हैं कि सब ठीक है।'

राणा ने मौजूदा स्थिति को बेहद विनाशकारी बताते हुए कहा कि 2015 के नेपाल भूकंप के बाद यह देश की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस घटना से बेहद दुखी है, लेकिन सरकार तत्काल सक्रिय होकर राहत और बचाव कार्यों में जुट गई है।

उन्होंने कहा, 'मैं नेपाल की सांसद भी हूं और हमने बचाव के लिए काफी काम शुरू कर दिया है। इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम बचाव अभियान चलाना है।'वहीं, भारत और नेपाल के संबंधों पर बात भी राणा ने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत जैसे पड़ोसी देश के साथ अपने संबंधों को पर नेपाल को नाज है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा केवल भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि यह लोगों, संस्कृतियों और परंपराओं को जोड़ती है।

उन्होंने कहा, ' भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी का संबंध है, जहां दोनों देशों के लोगों के बीच वैवाहिक रिश्ते भी हैं। दोनों देशों के संबंध केवल आज के दौर में विकसित नहीं हुए हैं, बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से दोनों देश लंबे समय से एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं।'